website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक रॉयल पत्रिका

वर्ष : 13 | अंक : 345 | पेज: 8 | जयपुर, शुक्रवार 21 नवंबर 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

एपस्टीन फाइलें जारी करने को तैयार:

राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल पर किए दस्तख़त, 30 दिनों में दस्तावेज़ होंगे सार्वजनिक

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राजनीति में हलचल मचाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन मामले से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कांग्रेस द्वारा पहले ही पास किए जा चुके इस बिल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) को 30 दिनों के अंदर एपस्टीन की जांच से जुड़ी सभी जानकारियों को खोजने और डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में जारी करना अनिवार्य होगा। लंबे समय तक बिल का विरोध करने के बाद ट्रंप द्वारा इसे मंजूरी देना कई सवाल उठाता है और राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहा है।

कांग्रेस में भारी बहुमत से पास हुआ बिल

इससे पहले, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बिल को 427-1 के भारी बहुमत से पास किया था। उसके बाद सीनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी। वोटिंग से पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर दस्तावेज़ों को सार्वजनिक करने में देरी कराने का आरोप लगाया। स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की कोई निजी भूमिका नहीं है और उनके पास "छिपाने के लिए कुछ भी नहीं" है। हालांकि, उन्होंने डेमोक्रेट्स की आलोचना करते हुए कहा कि वे चुनावी माहौल के बीच इस कदम को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रंप का रुख बदला, रिपब्लिकन सांसदों को दी अनुमति

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को जारी करने के

खिलाफ था। लेकिन अचानक रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि वे इस बिल के पक्ष में वोट कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि एपस्टीन का असली संबंध डेमोक्रेट्स से था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर ट्रंप ने लिखा कि एपस्टीन जीवनभर डेमोक्रेट रहे और उन्होंने डेमोक्रेट नेताओं को हजारों डॉलर दान किए। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कई डेमोक्रेट नेताओं के नाम भी गिनाए, जिनके साथ एपस्टीन के कथित संपर्क रहे थे, जिनमें बिल क्लिंटन, लैरी समर्स, रीड हॉफमैन, हकीम जेफ्रीज और स्टेसी प्लास्केट शामिल हैं।

DOJ ने पहले ही सौंपे 50,000 पेज के दस्तावेज़

ट्रंप ने दावा किया कि उनके कहने पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पहले ही कांग्रेस को लगभग 50,000 पेज के दस्तावेज़ सौंप चुका है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन ने एपस्टीन से संबंधित "एक भी फाइल" प्रदान नहीं की और न ही इस विषय पर कभी खुलकर बात की। ट्रंप के मुताबिक, फाइलों के जारी होने से कई डेमोक्रेट नेताओं और एपस्टीन के बीच के रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी।

ट्रंप का आरोप – "एपस्टीन मुद्दा डेमोक्रेट्स को ज्यादा प्रभावित करता है"

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने एपस्टीन मुद्दे का राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग किया, जबकि यह मुद्दा उन्हें रिपब्लिकन पार्टी से ज्यादा प्रभावित करता है। ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेट्स इस मुद्दे को उछालकर उनकी "शानदार उपलब्धियों" से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सरकार की कई उपलब्धियों का जिक्र किया—मजबूत सीमाएं, डीईआई को समाप्त करना, रिकॉर्ड मुद्रास्फीति पर रोक, कर कटौती, आठ युद्धों का अंत, सेना का पुनर्निर्माण और ईरान की परमाणु शक्ति को रोकना। ट्रंप ने यह भी कहा कि हाल ही में सरकारी शटडाउन पर भी उनकी पार्टी ने डेमोक्रेट्स को "बहुत बड़ी हार" दी है।

अब तक का सबसे बड़ा हमला:

रूस ने पूरी रात यूक्रेन में मचाई तबाही, घातक हथियारों से बड़ा वार—नाटो को सीधा संदेश!

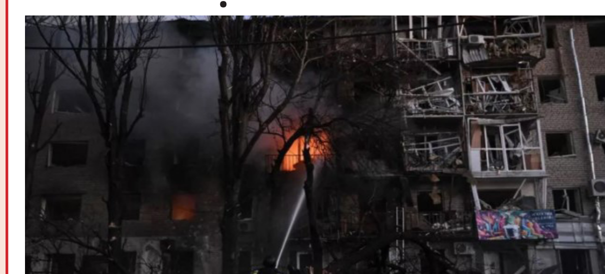

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आग लगातार भड़कती जा रही है। बीते 48 घंटों में रूस ने जिस पैमाने पर हमला किया है, उसे पिछले कई महीनों का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी हमला बताया जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 524 हवाई हमले किए, जिसने देश के तीन प्रमुख शहरों में भारी तबाही मचाई और लोगों में दहशत फैला दी। विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला केवल यूक्रेन पर नहीं, बल्कि नाटो देशों के लिए पुतिन की खुली चेतावनी है।

नाटो पर पुतिन का 'प्रतिकारात्मक संदेश'

इस तीव्र हमले से पहले नाटो ने रूसी सीमा के करीब बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया था। इससे रूस भड़क गया और पुतिन ने मंगलवार देर रात यूक्रेन पर घातक जवाबी हमला किया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम रूस का आखिरी अल्टीमेटम जैसा है—अगर नाटो ने दखल जारी रखा, तो हालात महायुद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस ने हाल ही में रूस के खिलाफ कड़ा स्वर अपनाते हुए सैन्य चेतावनियां जारी की थीं, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया है।

यूक्रेन के तीन शहरों पर आग का कहर

यूक्रेन के गृहमंत्री इहोर क्लिमेंको के मुताबिक रूस ने जानबूझकर आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया। हमलों में आवासीय कॉलोनियां, शिक्षा संस्थान और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर सीधे वार किया गया।

सबसे भयावह स्थिति टेरनोपिल में देखने को मिली, जहां दो नौ-मंजिला इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। एक इमारत में भीषण आग लगी और कई मंजिलें ढह गईं। कई बच्चों सहित दर्जनों नागरिक मारे गए।

रूस ने बरसाई मिसाइलें और ड्रोन

यूक्रेनी सेना की रिपोर्ट के अनुसार, 18 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर 19 नवंबर सुबह तक रूस ने लगातार हवाई हमले किए। इस दौरान रूस ने 48 मिसाइलें, 476 आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमले की वजह से कीव, टेरनोपिल और खारकीव में भारी तबाही हुई। इसे देखते हुए रोमानिया ने तुरंत दो Eurofighter Typhoon और दो F-16 फाइटर जेट पेट्रोलिंग पर भेजे। हमले के बाद पोलैंड के रिजेशो और ल्यूबलीन एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।

अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

एनडीए के शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया

-कहा, "आशा है नई सरकार बिहार को बेहतर दिशा देगी"

बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद विपक्ष की ओर से पहली प्रतिक्रिया पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आई है। मंगलवार (20 नवंबर) को पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से नई सरकार को बधाई दी और कई महत्वपूर्ण बातें लिखीं।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा—"आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नई सरकार जिम्मेदारी के साथ लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरकर अपने वादों और ऐलानों को पूरा करेगी। साथ ही बिहार के

लोगों के जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव भी लाएगी।" तेजस्वी के इस संदेश को राजनीतिक गलियारों में एक परिपक्व प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि वह लगातार एनडीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के मौके पर उनका यह रुख संयमित और रचनात्मक दिखाई दिया।

नतीजों से पहले तेजस्वी का आत्मविश्वास

चुनाव परिणाम आने से पहले तेजस्वी यादव बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा तक कर दिया था कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। लेकिन 14 नवंबर को आए नतीजों ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा—जहाँ एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, वहीं आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं।

नीतीश कुमार की रिकॉर्ड वापसी

20 नवंबर को हुए शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार ने लगातार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद संभालकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन करते हुए 26 नए मंत्रियों को जगह दी है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव का संदेश यह दर्शाता है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के बाद भी वह बिहार के विकास को लेकर सकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि नई एनडीए सरकार जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरती है।

शपथ ग्रहण में पीएम मोदी का अनोखा अंदाज़

-झुककर किया शुक्रिया, गमछा लहराकर बढ़ाया उत्साह

पटना। नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नया इतिहास रचा। पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पूरे समारोह में पीएम मोदी का अलग ही अंदाज़ देखने को मिला जिसने लोगों का दिल जीत लिया।

पीएम मोदी का देसी अंदाज़, लोगों में भरा जोश

शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर तक अपना गमछा लहराते दिखाई दिए। उनका यह देसी अंदाज़ देखते ही दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग तालियां बजाकर और जयकारे लगाकर उनका स्वागत करने लगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने समारोह में मौजूद लोगों के सामने कई बार झुककर आभार व्यक्त किया और उन्हें नमन किया। उनके इस विनम्र और भावनात्मक अंदाज़ ने उपस्थित लोगों को प्रभावित कर दिया। समारोह के दौरान पीएम मोदी और नीतीश कुमार कई बार एक-दूसरे से बातचीत करते भी दिखे और दोनों ही नेताओं के चेहरे पर प्रचंड जीत की खुशी साफ झलक रही थी।

चुनाव प्रचार में भी पसंद आया था पीएम का बिहारी स्टाइल

शपथ ग्रहण से पहले चुनावी रैलियों के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी का बिहारी अंदाज़ काफी चर्चित रहा था। उन्होंने कई बार नीतीश कुमार को "भाई" कहकर संबोधित किया और महिलाओं को भरोसा दिलाया कि "दो भाई"—नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार—उनकी सेवा और सम्मान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान गमछा लहराते हुए उनका वही अंदाज़ लोगों को खासा पसंद आया था, जो अब शपथ ग्रहण समारोह में फिर देखने को मिला।

बिहार की जनता ने नीतीश–मोदी की जोड़ी पर जताया भरोसा

बिहार के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साबित किया कि जनता ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर पूरा विश्वास जताया है। लोगों ने एनडीए को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता सौंपी। शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कुल 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में तीन महिलाओं को स्थान दिया गया है और कई नए चेहरों को भी मौका मिला है।

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, "यह बिहार के विकास की जीत है"

पटना । जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए देशभर से कई बड़े नेता पटना पहुंचे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गांधी मैदान में आयोजित समारोह में मौजूद रहे।

पटना पहुंचीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता—"यह लोगों के भरोसे की जीत है"

पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह लोगों के भरोसे और सरकार की कोशिशों की जीत है। उन्होंने इसे बिहार के विकास की जीत बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए के नेतृत्व और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार एक बार फिर सुशासन और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा और बाबा महाकाल से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

दसवीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, बनाया नया रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि पटना और पूरे बिहार में उत्सव जैसा माहौल है। नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने नीतीश कुमार और बिहार की जनता को इस जनादेश के लिए बधाई दी।

शपथ ग्रहण में शामिल हुए कई बड़े नेता

पटना के गांधी मैदान में आयोजित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह की भव्यता ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया।

एनडीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, गीतों से हुआ स्वागत

गांधी मैदान में शपथ ग्रहण देखने के लिए एनडीए के हजारों कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं में खास उत्साह इस बात को लेकर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दूसरी ओर, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने अपने गीतों से कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उनके प्रदर्शन से माहौल और भी जीवंत हो गया और समारोह में उत्साह की लहर दौड़ गई।

'कानून-व्यवस्था के ढोल पीटने वाली सरकार...' दादरी मॉब लिंचिंग केस पर ओवैसी का वार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दादरी मॉब लिंचिंग मामले को लेकर सरकार ने केस वापस लेने का निर्णय लिया है। इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दखल करार देते हुए कहा कि इस तरह के कदम लोकतंत्र की नींव को कमजोर करते हैं। दादरी निवासी मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, और अब इस केस के आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया गया है।

ओवैसी ने क्या कहा?

ओवैसी ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "कानून-व्यवस्था के ढोल पीटने वाली सरकार का यह निर्णय उसका असली चेहरा सामने लाता है, जो हमेशा दोषियों और मुजरिमों के साथ खड़ी दिखाई देती है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय व्यवस्था को राजनीतिक लाभ के लिए प्रभावित करना न केवल पीड़ित परिवार के साथ अन्याय है, बल्कि देश के सामाजिक ढांचे पर भी गहरा असर डालता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले आगे चलकर गंभीर परिणाम दे सकते हैं।

'अब लिंचिंग हुई आम बात' — ओवैसी

AIMIM प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा कि 2015 में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग होने के बाद आज देश में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा, "अखलाक़ पर गौ-मांस का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी लिंचिंग कर दी गई थी। उसका परिवार आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाया। दस साल में किसी को सज़ा नहीं मिली और अब योगी सरकार आरोपियों पर से केस वापस ले रही है, इसे 'सामाजिक सद्भाव' का नाम दिया जा रहा है। नाइंसाफी की बुनियाद पर सद्भाव संभव नहीं।" ओवैसी ने आगे कहा कि भाजपा का असली चेहरा यही है कि वह हमेशा दोषियों का साथ देती नजर आती है।

क्या थी दादरी की घटना?

साल 2015 में दादरी में गौ-मांस की अफवाह फैलने के बाद भीड़ ने अखलाक के घर पर धावा बोल दिया था। उस पर घर में गौ-मांस रखने का आरोप लगाया गया था। भीड़ ने उसे बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह पूरी घटना परिवार के सामने हुई। अखलाक को बचाने की कोशिश में उसके बेटे की भी पिटाई की गई, हालांकि उसे मामूली चोटें आई थीं। यह मामला देशभर में धार्मिक उन्माद और मॉब लिंचिंग पर बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की रिटायर उम्र एक साल बढ़ाने का दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साल बढ़ाने का महत्वपूर्ण आदेश दिया। अब न्यायिक अधिकारी 60 की जगह 61 वर्ष में रिटायर होंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार खुद इसके लिए तैयार है, तो न्यायिक अधिकारियों को यह लाभ देने में हिचक क्यों? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने जिला अदालत के जजों की रिटायर उम्र बढ़ाने का विरोध किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को राज्य सरकार और हाई कोर्ट रजिस्ट्री से उस याचिका पर जवाब माँगा था जिसमें रिटायरमेंट उम्र 60 से 61 करने से इनकार को चुनौती दी गई थी। 26 मई को भी सीजेआई की बेंच स्पष्ट कर चुकी थी कि सेवानिवृत्ति

आयु 61 करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी हों या राज्य के अन्य कर्मचारी—सभी का वेतन एक ही सरकारी खजाने से आता है। राज्य कर्मचारियों की रिटायर उम्र 62 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट के जज भी 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अब जिला कोर्ट के जजों की उम्र बढ़ाकर 61 कर दी गई है, जिससे एक साल का अंतर रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की अंतिम सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की है।

'भारत-रूस संबंधों को कमजोर करने की कोशिश...' अमेरिका के बैन पर रूसी राजदूत का बयान

मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। इस दौरे से पहले मॉस्को ने भारत को एक बड़ा सैन्य प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत रूस ने अपनी पांचवीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की तकनीक साझा करने की पेशकश की है। इसी बीच भारत-रूस संबंधों को लेकर भारत में तैनात रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने महत्वपूर्ण बयान जारी किया है।

मॉस्को बोले—भारत को देंगे बेहतर डील

अलिपोव ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा बनाई जा रही बाधाओं के बावजूद भारत आज भी रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। उन्होंने कहा कि रूस आगे भी भारत को ऊर्जा संसाधनों की खरीद के लिए लाभकारी सौदे देने के लिए हमेशा तैयार है। राजदूत के अनुसार, पश्चिमी राष्ट्र लगातार भारत पर यह दबाव बना रहे हैं कि वह रूस से तेल और गैस की खरीद कम करे, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देगा और सप्लाई जारी रखेगा।

अमेरिका का एक्शन—दो रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध

रूसी एजेंसी TASS के मुताबिक, डेनिस अलिपोव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। उन्होंने माना कि पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार और मजबूत हुआ है। अमेरिका ने रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोईल पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसके बावजूद राजदूत ने दावा किया कि भारत के लिए रूसी तेल की सप्लाई जारी रहेगी और रूस भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार बना रहेगा।

भारत-रूस रिश्तों पर अलिपोव का बड़ा बयान

भारत-रूस संबंधों के बारे में अलिपोव ने कहा कि पश्चिमी देशों के दबाव का दोनों देशों की साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा, "भारत-रूस संबंधों को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा मुद्दों को थोपने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन भारत ने इन प्रयासों का मजबूती से मुकाबला किया है।" अलिपोव ने भारत की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दरकिनार कर लगाए गए अवैध और एकतरफा प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यही भारत-रूस संबंधों की मजबूती का संकेत है।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

शराब की भ्रामक पैकिंग: आकर्षक टेट्रा पैक में छिपा नया खतरा

शराब की भ्रामक पैकिंग एक नया खतरा बनकर उभर रही है। शराब सेहत के लिए कितनी खतरनाक होती है, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मुनाफ़े के लालच में शराब कंपनियां अब ऐसे हथकंडे अपना रही हैं जो समाज के लिए और भी घातक साबित हो सकते हैं। हाल के दिनों में कुछ कंपनियों ने शराब को इस तरह के आकर्षक टेट्रा पैक में बेचना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल जूस या किसी अन्य शीतल पेय जैसा दिखता है। यह न सिर्फ उपभोक्ता को गुमराह करने वाला तरीका है, बल्कि बच्चों और किशोरों के लिए अनजाने में बड़ा खतरा भी बन सकता है। जब कोई पैकिंग जूस जैसी हो, उस पर स्पष्ट चेतावनी न हो और डिजाइन भी साफ-सुथरा व रंगीन हो, तो कोई भी यह अनुमान लगाना मुश्किल समझेगा कि इसके भीतर शराब है। यही कारण है कि यह पैकिंग किसी मासूम बच्चे के हाथों तक भी पहुंच सकती है और इससे हादसे की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। देश की शीर्ष अदालत ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि शराब को केवल राजस्व का साधन मानने की सोच बेहद ख़तरनाक है। अदालत ने पाया कि कुछ शराब कंपनियां जूस जैसे दिखने वाले टेट्रा पैक में शराब बेच रही हैं, जिससे न सिर्फ उपभोक्ता भ्रमित हो रहे हैं, बल्कि यह छात्रों तक भी आसानी से पहुंच रहा है। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी ऐसी पैकिंग देखकर आकर्षित हो सकते हैं और माता-पिता भी एक नजर में यह पहचान नहीं पाते कि पैक में शराब है। इस तरह की पैकिंग न सिर्फ भ्रामक है बल्कि सामाजिक नैतिकता और उपभोक्ता सुरक्षा—दोनों के साथ खिलवाड़ है। यह मुद्दा मूल रूप से अदालत के सामने दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क विवाद के कारण आया था, लेकिन सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि असल चिंता इससे कहीं बड़ी है। सिस्टम की अनदेखी और नियमन की कमी ने शराब कंपनियों को ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। यह स्थिति बताती है कि जिम्मेदार एजेंसियों ने न तो नियमों को सख़्ती से लागू किया और न ही बाजार में उपलब्ध उत्पादों की सही निगरानी की। शराब की पैकिंग पर चेतावनी, स्पष्ट संकेत और इसके स्वरूप को नियंत्रित करने के नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन जब तक उनकी सख़्ती से पालना नहीं होगी, तब तक ऐसी समस्याएं सामने आती रहेंगी। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आज पैकिंग केवल मार्केटिंग का माध्यम नहीं रही, बल्कि उपभोक्ता के मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली हथियार बन चुकी है। कंपनियां यह भली-भांति जानती हैं कि आकर्षक रंग, डिजाइन और पैटर्न उपभोक्ता को लुभाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब यही हथियार शराब की ओर खींचने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो यह समाज के लिए और भी हानिकारक हो जाता है। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पहले से बढ़ रही है।

जीपीएस स्पूफिंग: खामोश साइबर हमला जो बिना आवाज़ के विमान, जहाज, ड्रोन और पूरे सुरक्षा तंत्र को पंगु बना सकता है

-नकली जीपीएस सिग्नल से दिशा और सिस्टम दोनों भ्रमित

आधुनिक दुनिया में युद्ध का रूप बदल चुका है। अब दुश्मन न तो सीमाओं पर दिखाई देता है और न ही उसकी बंदूकों की आवाज़ सुनाई देती है। आज के दौर में सुरक्षा को सबसे बड़ा ख़तरा उन हमलों से है जो अदृश्य, खामोश और तकनीकी रूप से बेहद पैने होते हैं। ऐसे ही खतरों में सबसे बड़ा नाम है GPS Spoofing (जीपीएस स्पूफिंग)—एक ऐसी तकनीक जो बिना हथियार चलाए किसी पूरे देश की सुरक्षा, परिवहन, सेना और संचार प्रणाली को पंगु बना सकती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में हुए घटनाक्रम ने इसी खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। 800 से ज़्यादा फ्लाइटें अचानक बाधित हुईं, रनवे की दिशा बदलती हुई दिखाई दी, पायलटों की स्क्रीन पर हर पल गलत लोकेशन आने लगी और कुछ ही सेकंड में विमान के क्रैश होने का real risk सामने आ गया। यह कोई साधारण तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी—बल्कि एक हाई-टेक साइबर अटैक, जिसमें जीपीएस सिग्नलों से छेड़छाड़ की गई थी।

क्या हुआ था उस रात?—एक खामोश हमला, जिसकी कोई आवाज़ नहीं

उस रात पायलटों ने जो देखा, वह किसी साइंस-थ्रिलर फिल्म जैसा दृश्य था। रनवे की जगह स्क्रीन पर खुला मैदान दिखाई देने लगा। विमान की लोकेशन हर कुछ सेकंड में 200–300 मीटर उछल रही थी। ऑटोपायलट अचानक गलत दिशाओं में मोड़ने लगा। ऊंचाई (Altitude) के आंकड़े भी अनियमित हो गए। पायलटों को फ़ौरन GPS आधारित ऑटो-नेविगेशन बंद करके मैनुअल नियंत्रण संभालना पड़ा, वरना कुछ ही क्षणों में यह घटना किसी बड़े विमान हादसे में बदल सकती थी। यह घटना दिखाती है कि— हमले का कोई धुआं नहीं, आवाज नहीं,

विस्फोट नहीं—लेकिन नुकसान आसमान से जमीन तक फैल सकता था।

GPS Spoofing आखिर है क्या?

सामान्य शब्दों में समझें तो जीपीएस स्पूफिंग उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति को उसकी आंखों पर नकली चश्मा पहनाकर गलत दिशा में भेज दिया जाए। GPS Spoofing वह तकनीक है जिसमें कोई हमलावर असली GPS satellites की signals को ओवरपावर करके नकली signals भेजता है, ताकि सिस्टम उसे असली समझकर गलत लोकेशन पढ़ने लगे। यह हमलावर को यह ताकत देता है कि वह— विमान को रनवे से हटाकर दूसरी दिशा की ओर ले जाए, जहाजों को समुद्र में गलत रास्ते पर बहका दे, मिसाइल का target बदल दे, ड्रोन को क्रैश करा दे, पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भ्रमित कर दे, बिजली ग्रिड और बैंकिंग नेटवर्क को अव्यवस्थित कर दे, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि— GPS Spoofing को करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ किलोवॉट का रेडियो स्पूफर, ऐन्टेना और साइबर तकनीक ही काफी है।

GPS पर दुनिया की निर्भरता: जितनी बढ़ी, जोखिम उतना गहरा

आज दुनिया का हर आधुनिक सिस्टम GPS पर खड़ा है: एविएशन सिस्टम, शिप नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटेड ड्रोन, बैंकिंग नेटवर्क (टाइम स्टैम्प GPS पर चलता है), इंटरनेट सिंक्रोनाइज़ेशन, बिजली ग्रिड, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, दुनिया में हर सेकंड 4 ट्रिलियन से ज़्यादा GPS आधारित लोकेशन या टाइमिंग रिक्वेस्ट प्रोसेस होती हैं। इसलिए यदि GPS में कुछ सेकंड का झटका लगे, तो न सिर्फ विमान बल्कि पूरा देश भी प्रभावित हो सकता है।

GPS Spoofing कैसे किया जाता है?—तकनीक के अंदर झांकें

GPS स्पूफिंग किसी बच्चे का खेल नहीं, लेकिन यह अत्यधिक जटिल भी नहीं है।

आम तौर पर इसमें चार चरण होते हैं:

लक्ष्य का चयन (Target Acquisition): हमलावर पहले यह चुनता है कि उसे किस सिस्टम को भ्रमित करना है—

जैसे विमान, जहाज, ड्रोन या ट्रैफिक नेटवर्क।

असली GPS signals को स्कैन करना: हमलावर GPS signals की फ्रीक्वेंसी देखता है (L1, L2 आदि),

ताकि उसी जैसी नकली फ्रीक्वेंसी generate कर सके।

नकली signals का निर्माण (Fake Signal Generation): उन्नत रेडियो ट्रांसमीटर, SDR (Software Defined Radio) और कंप्यूटर algorithms की मदद से नकली GPS डेटा तैयार किया जाता है।

Fake signals को इतनी शक्ति से भेजना कि असली GPS signals दब जाएं: GPS signals अंतरिक्ष से आते हैं, इसलिए उनकी शक्ति बहुत कम होती है। हमलावर इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह पास या आसपास से तेज़ power वाले नकली signals भेजकर असली signals को ओवरपावर कर देता है। कुछ सेकंड में पूरा सिस्टम विश्वास करने लगता है कि वही लोकेशन सही है।

GPS Spoofing बनाम GPS Jamming: दोनों में क्या फर्क है?

तकनीक	क्या करती है?	खतरा
GPS Jamming	GPS signals को ब्लॉक या बाधित करती है	सिस्टम फेल हो जाता है, लेकिन गलत डेटा नहीं बनता
GPS Spoofing	नकली GPS डेटा भेजता है ताकि सिस्टम गलत दिशा में जाए	बेहद खतरनाक—system गलत निर्णय लेता है

GPS जेमर सिर्फ "अंधेरा" पैदा करता है, जबकि GPS स्पूफर गलत रास्ता दिखाता है, जो कहीं ज़्यादा खतरनाक है।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: दुनिया पहले ही इसका निजी अनुभव कर चुकी है, दुनिया भर में GPS स्पूफिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं:

रूस और यूक्रेन में GPS युद्ध: युद्ध के दौरान दोनों देशों ने एक-दूसरे के ड्रोन को स्पूफिंग से गिराया। कई ड्रोन पूरी तरह गलत जगह उतरते पाए गए।

ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को 'उतार लिया': 2011 में ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी ड्रोन RQ-170 Sentinel को GPS spoofing करके नियंत्रित किया और उसे सुरक्षित लैंड करा लिया।

शिपिंग उद्योग में खतरे: काला सागर और मध्य-पूर्व में जहाजों को गलत रूट पर भेजने के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई बार जहाजों की लोकेशन जमीन पर दिखाई गई, जबकि वे समुद्र में थे।

भारत के लिए चेतावनी: हमारा GPS इंफ्रास्ट्रक्चर कितना संवेदनशील?

भारत की सुरक्षा प्रणालियां भी GPS आधारित हैं— नीचे दिए गए क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील हैं:

भारत का एविएशन सेक्टर: लगभग 90% नेविगेशन सिस्टम GPS आधारित हैं।

देश में एयरपोर्ट छोटे रेडियो सिग्नलों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं।

सैन्य प्रणाली

मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन, नौसेना के जहाज, आर्मी के लोकेशन ट्रैकर्स, इनमें से कई GPS पर निर्भर हैं।

नागरिक क्षेत्र

बैंकिंग टाइम स्टैम्प, बिजली ग्रिड, ट्रैफिक सिस्टम, वाणिज्यिक डिलीवरी, GPS में मामूली बदलाव भी बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

क्यों GPS Spoofing आधुनिक साइबर युद्ध का 'नया हथियार' बन रहा है?

सस्ता है: कुछ लाख रुपये में भी उन्नत स्तर का स्पूफर बनाया जा सकता है।

पता लगाना मुश्किल है: हमले की कोई आवाज़, धुआं या प्रत्यक्ष सबूत नहीं होता।

दूरी से किया जा सकता है: हमलावर कई किलोमीटर दूर बैठकर सिस्टम को भ्रमित कर सकता है।

पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन: लोकतंत्र पर चोट, सैन्य वर्चस्व की वापसी और आसिम मुनीर की बढ़ती ताक़त की नई कहानी

-संशोधन से सेना मजबूत, न्यायपालिका और लोकतंत्र पर खतरे बढ़े

पाकिस्तान की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ लोकतंत्र और सैन्य सत्ता के बीच की खींचतान एक बार फिर खुले रूप में सामने आ गई है। शहबाज़ शरीफ़ सरकार द्वारा संविधान में 27वें संशोधन को मंजूरी दिलाने के बाद पूरा देश गरमा गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह संशोधन पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाओं, खासकर न्यायपालिका और प्रांतीय स्वायत्तता पर सीधा हमला है। जबकि सरकार इसे "सुधार" बताकर बचाव कर रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह संशोधन किसके हित में है? और क्या यह पाकिस्तान को फिर उसी सैन्य हुक़ूमत वाले रास्ते पर ले जाएगा, जिस राह पर कभी जनरल ज़िया-उल-हक़ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ चले थे?

संशोधन का राजनीतिक संदर्भ — सत्ता के गलियारों में नए समीकरण

27वां संशोधन उस समय लाया गया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गहरी संकट में है, राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर है और जनता का भरोसा तमाम संस्थाओं से डगमगा चुका है। ऐसे परिदृश्य में संविधान से छेड़छाड़ एक बड़े राजनीतिक एजेंडे की ओर इशारा करती है। सबसे ज़्यादा चर्चा में वो प्रावधान हैं जिनसे सेना और न्यायपालिका की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की योजना है। पाकिस्तान के संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि संशोधन भले ही कई क्षेत्रों को छूता है, लेकिन इसका वास्तविक लक्ष्य आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर की शक्तियों को और बढ़ाना है। विपक्ष का आरोप है कि यह संशोधन "सिर्फ सुधार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक स्क्रिप्ट" है, जिसमें सेना को पहले से भी ज़्यादा मज़बूत बनाकर नागरिक शासन को हाशिये पर धकेला जा रहा है।

आख़िर 27वें संशोधन में क्या है? — विवाद की जड़

विधेयक में कई ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जिन पर पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था दशकों से संवेदनशील रही है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

दोहरी नागरिकता पर पुनर्विचार: कुछ श्रेणियों में दोहरी नागरिकता वाले लोगों को सरकारी नियुक्तियों में अनुमति देना। आलोचकों के अनुसार, यह संशोधन सेना और नौकरशाही में विशेष पदों पर "अपनों की तैनाती" का रास्ता खोल सकता है।

संवैधानिक अदालत का गठन: एक समानांतर न्यायिक ढाँचा तैयार करने की योजना है। विपक्ष का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास है।

प्रांतीय हिस्सेदारी में कटौती: नेशनल फ़ाइनेंस कमीशन (NFC) अवॉर्ड में प्रांतों को मिलने वाले राजस्व में कमी की संभावना। यह पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान पहले ही "केन्द्र की दादागिरी" का आरोप लगाते रहे हैं।

शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण पर केन्द्र की शक्ति बढ़ाना: अब तक ये विषय प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में आते थे।

संशोधन के बाद संघीय सरकार के हस्तक्षेप का मार्ग खुल जाएगा।

चुनाव आयोग की नियुक्ति में बदलाव: यह प्रावधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विपक्ष को डर है कि इससे चुनाव आयोग "सरकार–सेना के प्रभाव" में आ जाएगा।

अनुच्छेद 243 में संशोधन — सबसे विवादित बिंदु: अनुच्छेद 243 पाकिस्तान में सेना की कमान, अधिकार और जवाबदेही तय करता है। संशोधन के बाद आर्मी चीफ की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हो जाएगी।

यही वह संवैधानिक बिंदु है जिसे लेकर नेपाल से लेकर वाशिंगटन तक राजनीतिक विश्लेषक चिंतित हैं।

क्यों माना जा रहा है कि असली मकसद आर्मी चीफ़ की ताक़त बढ़ाना है?

आलोचक यह तर्क दे रहे हैं कि: संशोधन का संरचना–तंत्र सेना के हितों से मेल खाता है। कई प्रावधानों को ऐसे समय लाया गया है जब आर्मी चीफ का कार्यकाल निर्णायक मोड़ पर है। अनुच्छेद 243 में परिवर्तन से आर्मी चीफ की भूमिका "कमान्डर" से बढ़कर "सुपर एग्जीक्यूटिव" जैसी हो जाएगी। यह संशोधन सेना को नागरिक सरकार और न्यायपालिका पर अधिक प्रभावशाली बनाता है। विपक्षी दलों को डर है कि पाकिस्तान में सेना एक बार फिर "छाया शासन" की जगह "प्रत्यक्ष और मजबूत सत्ता" की ओर लौट आएगी।

क्या पाकिस्तान जिया-उल-हक़ और मुशर्रफ़ मॉडल की ओर?

पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि हर बार जब सैन्य नेतृत्व को संवैधानिक रूप से अधिक अधिकार दिए गए, तब देश ने लोकतंत्र से दूरी ही बनाई।

जिया-उल-हक़ मॉडल: संविधान में बदलाव कर खुद को जीवनभर का राष्ट्रपति बनाने की कोशिश।

इस्लामीकरण का एजेंडा आगे बढ़ाकर अदालतों को नियंत्रित करना।

नागरिक सरकारों को कमजोर करना।

मुशर्रफ़ मॉडल: 17वां संशोधन लाकर संसद, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों को अपनी मर्ज़ी के अनुसार ढालना।

संसद के ऊपर राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। अब विशेषज्ञ 27वें संशोधन को इन दोनों मॉडलों का आधुनिक संस्करण बता रहे हैं।

असली विवाद — न्यायपालिका क्यों भड़की?

पाकिस्तान की न्यायपालिका पहले से ही सरकार और सेना के बीच विवादों का एक प्रमुख केंद्र रही है। नई संवैधानिक अदालत का गठन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जा रहा है।

जजों का तर्क है कि: इससे दो समानांतर न्यायिक प्रणालियाँ बन जाएँगी। संवैधानिक मामलों पर सेना का प्रभाव बढ़ जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और कई वरिष्ठ वकीलों ने इसके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम सहित कई दलों ने इसे "लोकतंत्र के लिए ख़तरा" कहा है। उनके मुख्य तर्क हैं: राजनीतिक ढाँचे को सेना-प्रधान बनाने की कोशिश। नागरिक सरकार के अधिकार सीमित होंगे। चुनाव आयोग कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाएगा।

भर्ती में खेल प्रमाण–पत्रों का फर्जीवाड़ा बढ़ता संकट, कब तक चलता रहेगा यह 'खेल' और कब मिलेगी खिलाड़ियों को सही न्याय

-डिजिटल वेरिफिकेशन से ही खेल कोटा होगा पारदर्शी और सुरक्षित

सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, मेरिट और न्याय का सिद्धांत हमारे प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ माना जाता है। भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य केवल रिक्त पदों को भरना नहीं होता, बल्कि योग्य, मेहनती और काबिल युवाओं को उनके हक तक पहुँचाना होता है। इसी सोच के तहत खेल कोटे की व्यवस्था बनाई गई थी — ताकि खेल के मैदान में देश-प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन दुखद हक़ीक़त यह है कि खेल कोटे में 'खेल' होने लगा है। हालिया जांच रिपोर्ट ने जो तस्वीर सामने रखी है, वह न सिर्फ चौंकाती है, बल्कि पूरी भर्ती प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। प्रदेशभर से 298 अभ्यर्थियों के आवेदन सिर्फ इस वजह से निरस्त किए गए क्योंकि उनके खेल प्रमाण–पत्र फर्जी या अपात्र पाए गए। सोचने वाली बात यह है कि यह केवल एक भर्ती की तस्वीर है। असल समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन 298 में से 100 से अधिक महिला अभ्यर्थी भी शामिल थीं। इससे साफ है कि फर्जीवाड़ा अब किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक व्यवस्थित और संगठित प्रवृत्ति बन चुका है। यह न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को दूषित करता है, बल्कि उन असली खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है, जिन्होंने खेल मैदान में पसीना बहाकर अपनी कला निखारी है।

खेल कोटा: उद्देश्य क्या था और हो क्या रहा है?

खेल कोटे का मूल मकसद था — खिलाड़ियों को सम्मान देना, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना, खेल भावना को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना, लेकिन जब फर्जी सर्टिफिकेट लेकर लोग खेल कोटे में कतार में खड़े होने लगें, तो यह न केवल व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में फैलती 'शॉर्टकट मानसिकता' का भी स्पष्ट प्रमाण है। आज तीरंदाजी, बॉक्सिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जूडो, खो-खो, कुश्ती — लगभग हर खेल में ऐसे प्रमाण–पत्र मिले हैं, जो असलियत की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। यह समस्या अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे वर्षों से जमा होता ढीलापन, निगरानी की कमी और कई जगह दिखती मिलीभगत है।

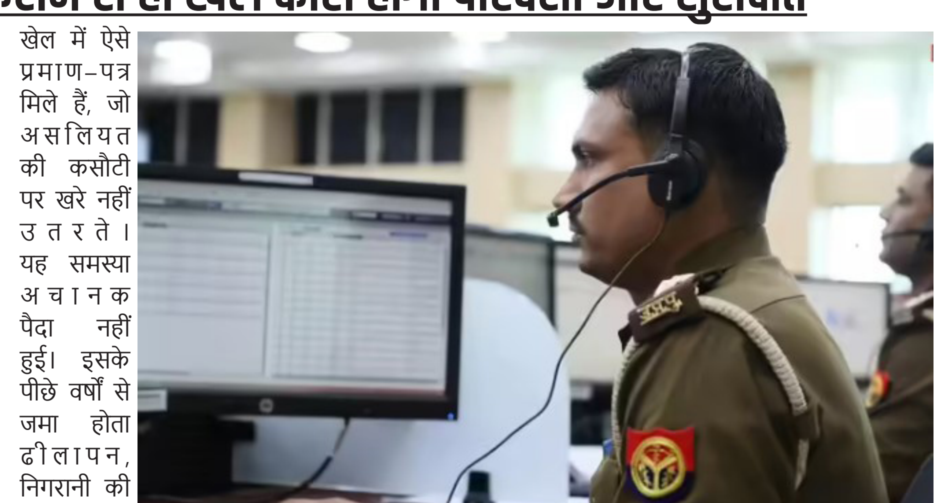

सबसे बड़ा सवाल — इतने वर्षों तक यह फर्जीवाड़ा चलता कैसे रहा?

यहां केवल अभ्यर्थियों को दोष देना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। कुछ मुख्य सवाल हैं जो व्यवस्था की कमज़ोरियों को उजागर करते हैं—

क्या खेल संघों का कोई मजबूत ऑडिट नहीं होता?: ज्यादातर फर्जी प्रमाण–पत्र वहीं से निकलते हैं जहां 'दरार' मौजूद होती है। यदि खेल संघों और प्रमाण जारी करने वाली संस्थाओं का समय–समय पर ऑडिट हो, तो फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो सकती है।

क्या प्रमाण–पत्र जारी होने का कोई डिजिटल रेकॉर्ड नहीं रखा जाता?: अब भी कई जगह कागज़ों पर निर्भरता है, जिसका फायदा उठाकर नकली प्रमाण–पत्र तैयार कर लिए जाते हैं।

क्या भर्ती विभाग प्रारंभिक चरण में ही दस्तावेज़ों की कठोर जांच नहीं करता? जब दस्तावेज़ों का सत्यापन अंतिम चरणों में होता है, तब तक फर्जी उम्मीदवार पूरी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। यह असली प्रतिभा का स्थान छीनने जैसा है।

क्या जिला स्तर पर खेल अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं? जवाबदेही तय न होने से सिस्टम में लापरवाही और भ्रष्टाचार पनपते हैं।

फर्जी सर्टिफिकेट: प्रतिभा के साथ सबसे बड़ा अन्याय

जब कोई फर्जी अभ्यर्थी असली खिलाड़ी के बराबर खड़ा हो जाता है, तो वह केवल एक व्यक्ति का हक नहीं छीनता, बल्कि पूरी खेल संस्कृति और भविष्य से खिलवाड़ करता है।

असली खिलाड़ी हतोत्साहित होते हैं: जो सुबह–शाम मैदान में मेहनत करते हैं, प्रतियोगिताएँ जीतते हैं, वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं।

परिवार का भरोसा टूटता है: खिलाड़ी परिवार बड़ी मुश्किल से बच्चे को खेल में आगे बढ़ाते हैं — आर्थिक बोझ, समय, मेहनत सब झोंककर। फर्जी सर्टिफिकेट इस भरोसे को तोड़ देते हैं।

खेलों का सम्मान कम होता है: जब समाज को यह पता चलता है कि फर्जी खिलाड़ी भी खेल कोटे से नौकरी पा सकते हैं, तो खेल कोटे का महत्व गिर जाता है।

प्रशासनिक प्रणाली अविश्वसनीय बनती है: लोगों को लगता है कि बिना खेल खेले भी सरकारी नौकरी मिल सकती है — यह धारणा अपराध को बढ़ावा देती है।

समस्या केवल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं — प्रशासनिक ढांचा भी उतना ही जिम्मेदार

यह मान लेना कि 298 फर्जी प्रमाण–पत्र सिर्फ अभ्यर्थियों की गलती है, एक अधूरा निष्कर्ष होगा। असलियत यह है कि— फर्जीवाड़ा चैनलाइज्ड होता है, प्रमाण–पत्र बनवाने के दलाल सक्रिय रहते हैं, कई जगह खेल संघों में भ्रष्टाचार दिखता है, जिला स्तर पर निगरानी बेहद कमजोर है, खेल विभाग और भर्ती विभाग के बीच डेटा साझा करने का अभाव है, फर्जी सर्टिफिकेट तभी बनते हैं जब कहीं न कहीं सिस्टम में ढील या मिलीभगत होती है। इसलिए सुधार का रास्ता केवल अभ्यर्थियों को दंडित करने से नहीं निकलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा।

समाधान क्या? — डिजिटल वेरिफिकेशन ही सबसे प्रभावी रास्ता

समस्या जितनी गंभीर है, समाधान भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी कदम है — खेल प्रमाण–पत्रों का डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए यानी: हर खेल प्रमाण–पत्र एक यूनिक QR कोड से जुड़े प्रमाण का पूरा डेटा ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध हो, भर्ती विभाग सर्टिफिकेट स्कैन करते ही सत्यता जान सके, जारीकर्ता संस्था का नाम, तारीख, प्रतियोगिता का स्तर, खिलाड़ी की पहचान — सब एक जगह हो, यह कदम फर्जीवाड़े की 90% संभावनाएँ खत्म कर देगा।

इसके साथ कुछ और ठोस सुधार अनिवार्य हैं:

खेल संघों की जवाबदेही तय हो: प्रमाण–पत्र जारी करते समय वीडियो/फोटो रिकॉर्ड अनिवार्य गलत प्रमाण देने पर संघ पर कड़ी कार्रवाई संघों का वार्षिक ऑडिट

दस्तावेज़ सत्यापन भर्ती की पहली स्टेज में हो: अंतिम चरण में फर्जी प्रमाण पकड़े जाने से असली खिलाड़ियों का समय बर्बाद होता है। शुरुआत में ही कड़ा सत्यापन हो।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025

सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम से राजस्थान बनेगा जीसीसी एक्सीलेंस हब

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुमोदित राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) का पसंदीदा गंतव्य स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों का सशक्त बिजनेस इकोसिस्टम और किफायती ऑपरेशनल लागत के साथ-साथ इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी के प्रावधान इच्छुक कंपनियों को राजस्थान में जीसीसी की स्थापना के लिए आकर्षित करते हैं।

प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, किफायती ऑपरेशनल लागत जीसीसी निवेश के लिए अनुकूल -

सुदृढ़ बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल और निवेश अनुकूल नीतियों की विशेषताओं के साथ प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में गत दो वर्ष में सकारात्मक बदलाव आया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। एनसीआर रीजन और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के साथ कनेक्टिविटी राजस्थान

में जीसीसी निवेशकों की पहुंच बड़े औद्योगिक केन्द्रों और बाजारों तक उपलब्ध कराती है। साथ ही, देश के बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रमुख शहरों में साधनों एवं सेवाओं की किफायती ऑपरेशनल लागत भी निवेश को सुगम बनाती है।

राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग-

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 में जीसीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। इच्छुक आवेदकों को राजनिवेश सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन कमेटी (पीईसी) इन आवेदनों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा प्राथमिकता से 60 दिन की समय सीमा में प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पीएसी) को प्रस्तुत करेगी। यह अप्रूवल कमेटी भी 60 दिन की समय सीमा में अनुशंसा के आधार पर आवेदन पर निर्णय करेगी। कार्यकारी निदेशक रीको, पीईसी और प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पीएसी के अध्यक्ष होंगे। जीसीसी के आवेदनों के निस्तारण के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने में सहायक होगी नीति-

जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नवाचार, दक्षता और मूल्य सृजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 वर्ष 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5 लाख रोजगार सृजित करने के साथ भारत के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का 'आदर्श पड़ोसी, आदर्श समाज' अभियान, कल से भाईचारे का देंगे संदेश

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (JIH) राजस्थान ने समाज में बढ़ते अकेलेपन को दूर करने और आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल की है। संगठन ने "आदर्श पड़ोसी, आदर्श समाज" के नारे के साथ "पड़ोसियों के अधिकार" को लेकर दस-दिवसीय देशव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह मुहिम 21 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक पूरे देश में चलाई जाएगी।
गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमाअत के प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद नाज़िमुद्दीन ने बताया कि इस्लाम में पड़ोसियों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि क़ुरआन न केवल निकटम पड़ोसियों, बल्कि सहयात्री और साथ चलने वाले 'अस्थाई पड़ोसियों' के साथ भी अच्छे व्यवहार का आदेश देता है। इस मुहिम का उद्देश्य लोगों

को एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए प्रेरित करना है, ताकि समाज से गलतफहमियां दूर हों और हमदर्दी बढ़े।

बिना भेदभाव के चलेंगे कार्यक्रम

मीडिया सचिव डॉ. सैयद नासिर हसन ने बताया कि इस अभियान के दौरान धर्म के भेदभाव के बिना पड़ोसियों को जोड़ा जाएगा। मुहिम के तहत 'अपने पड़ोसी को जानें', चाय पार्टी (Tea Parties), मोहल्ला सफाई अभियान और रास्तों के अधिकारों पर जागरूकता रैलियां निकाली जाएंगी।

युवाओं और महिलाओं की रहेगी भागीदारी

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसमें चित्रकला, रील मेकिंग, भाषण और निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही, जयपुर में "विभिन्न धर्मों में पड़ोसियों के अधिकार" विषय पर एक विशेष सिंपोजियम भी आयोजित किया जाएगा। जमाअत के कार्यकर्ता घर-घर जाकर बीमारों और बुजुर्गों का हाल जानेंगे और उपहार भेंट करेंगे।

पांचवी बटालियन आरएसी के कांस्टेबल भर्ती—2025 का परिणाम जारी

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा आरएसी की पांचवी बटालियन में कांस्टेबल भर्ती—2025 (सामान्य) हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का वर्गवार परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। बटालियन के कमाण्डेन्ट चूनाराम जाट ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम राजस्थान पुलिस विभाग की वेबसाइट पर देख सकते है।

इसके साथ ही परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बरों की सूची कार्यालय कमाण्डेन्ट, पांचवी बटालियन आरएसी, घाटगेट हजूरी तोपखाना, जयपुर के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा दिसम्बर माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जावेगी जिसके लिए नियत तिथि व स्थान की सूचना पृथक से जारी की जावेगी।

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' और 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' की तैयारियों का किया व्यापक निरीक्षण

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। दिसंबर में आयोजित होने वाले 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' की तैयारियों की समीक्षा हेतु जेडीए सचिव निशान्त जैन एवं नगर निगम आयुक्त, डॉ. गौरव सैनी ने गुरूवार को टीम के साथ फील्ड में जाकर विस्तृत निरीक्षण किया। सचिव एवं आयुक्त ने बिड़ला मंदिर से अपना दौरा प्रारंभ किया जिसके बाद मोती डूंगरी रोड़ होते हुये जेएलएन मार्ग, वल्र्ड ट्रेक पार्क के साथ-साथ मालवीय नगर जोन, जगतपुरा जोन, सांगानेर जोन, एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल, पत्रिका गेट सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त मुकुट सिंह, उपायुक्त स्वास्थ्य ओम प्रकाश थानवी, अधीक्षण अभियन्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने शहर की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' एवं 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' की तैयारियों में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हों। उन्होंने निर्देश दिया कि सौंदर्यकरण के लिए

मुख्य मार्गों पर हैंगिंग प्लांट्स लगाए जाएं और सड़क किनारे के पौधों तथा पेड़ों की कटाई-छंटाई की जाए। दीवारों पर पेंटिंग, सार्वजनिक शौचालयों और लिटर बिन की सफाई, सड़क किनारे की सफाई और संकेत बोर्ड की मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। फ्लाईओवर को अधिक आकर्षक बनाने हेतु चित्रकारी और लाईटिंग के भी निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा, ताकि 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' की तैयारी में कोई कमी न रह जाए। निरीक्षण के दौरान शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से निर्माण मलबे और अन्य अवशेषों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने, अवैध एवं अस्थायी अतिक्रमणों को तुरंत हटाने, मुख्य मार्गों पर सभी स्ट्रीट लाइट्स को पूर्ण रूप से सुचारू करने के निर्देश दिये। साथ ही शहर में लगे अवैध होर्डिग को भी हटाने के निर्देश दिए

आयुक्त ने किया रात्रिकालीन निरीक्षणः-

नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। आयुक्त ने मैकेनाइज्ड रोड़ स्वीपिग मशीनों की कार्यप्रणाली को देखा और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि इन मशीनों द्वारा सड़कों की सफाई समुचित रूप से सुनिश्चित की जाये साथ ही निराश्रित गायों को पकड़कर हिगौनिया गौ-पुनर्वास केन्द्र में भिजवाने के निर्देश भी दिये। इस दौरान अधिशाषी अभियन्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने किया राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण

-हेल्पलाइन को 'नेक्स्ट जेन राजस्थान सम्पर्क' के रूप में तैयार करने के दिए निर्देश

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डेस्क पर जाकर स्वयं हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का गहन अवलोकन किया और वहां उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों को त्वरित निस्तारण एवं बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए आवश्यक सुझाव दिए। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को 'नेक्स्ट जेन राजस्थान सम्पर्क' के रूप में विकसित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जन शिकायतों के और त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और राजस्थान संपर्क को देश की सबसे प्रभावी एवं नागरिक-केंद्रित हेल्पलाइन बनाने का गौरव हासिल किया जाए।

नोडल अधिकारियों की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से होगी समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह विभागवार शिकायतों का डेटा तैयार कर संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा जाए, ताकि निस्तारण प्रक्रिया और तेज हो सके। प्रत्येक सचिव प्रतिदिन

कम-से-कम 10 लंबित शिकायतों की व्यक्तिगत समीक्षा करें तथा उसकी रिपोर्ट संबंधित मंत्रीगण को भेजें। विभागों में शिकायत निवारण हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से होगी।

शिकायत निस्तारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकाधिक उपयोग हो

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हर माह एक बार 'राजस्थान संपर्क दिवस' मनाया जाए, जिसमें डिजिटल माध्यमों से आमजन से सीधा संवाद किया जाए। साथ ही ई-मित्र/सीएससी लेवल एंटरप्रेन्योर के जरिए भी मुख्य सचिव स्तर पर जनता से जुड़ने की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत निस्तारण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकाधिक उपयोग हो, जिससे मानव संसाधन का सही इस्तेमाल हो और निस्तारण में तेजी आए। इसके लिए आईआईटी जोधपुर तथा एमएनआईटी जयपुर से संपर्क कर अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने की कार्यवाही की जाए। साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर चैटबॉट को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन राजस्थान संपर्क वेबसाइट एवं सोशल मीडिया हैंडल पर इन्फोग्राफिक्स जारी हों, जिनमें दर्ज शिकायतों की संख्या, निस्तारित शिकायतें तथा अन्य प्रासंगिक आंकड़े प्रदर्शित किए जाएं। सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित प्रकरणों की संतुष्टि का स्तर और अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। निरीक्षण के दौरान शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार डॉ. रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार डॉ. जोगाराम, निदेशक जन सेवाएं हर्ष सावनसुखा, ग्रुप हेड राजस्थान संपर्क जी.के. शर्मा, प्रभारी अधिकारी राजस्थान संपर्क पवन कुमार जांगिड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एनटीपीसी की पहल से सरकारी स्कूल में विज्ञान शिक्षा को मिला नया आयाम

-मनोहरपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नं.1 में शुरू हुई अत्याधुनिक प्रयोगशाला

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। छात्रों के लिए विज्ञान शिक्षा अब किताबों तक सीमित नहीं रहेगी। एनटीपीसी की शानदार पहल के तहत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नं.1 (अंग्रेजी माध्यम), मनोहरपुर में फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के अंतर्गत प्रदान की गई ये आधुनिक विज्ञान किटें अब छात्रों को प्रैक्टिकल विज्ञान से जोड़ने का नया मंच प्रदान करेंगी।
वही बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. महेंद्र पलसानिया, सोशल डेवलपमेंट एंड हेरिटेज एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन के निदेशक डॉ. शंकरलाल सैनी, इंजीनियर असरार अहमद, इंजीनियर नवीन निसार बारूदगर, समाजसेवी पुष्कर लाल सैनी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने फीता काटकर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. पलसानिया ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध करवाए गए माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स, मॉडल, माप-यंत्र और वैज्ञानिक उपकरणों से विद्यार्थी अब स्वयं प्रयोग कर विज्ञान की गहराई समझ सकेंगे। यह पहल बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्लेषण क्षमता और समस्या-समाधान कौशल को मजबूत करेगी। वही शिक्षकों ने बताया कि प्रयोगात्मक सामग्री उपलब्ध होने से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि तेजी से बढ़ी है और उनकी अवधारणात्मक समझ पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो रही है। उद्घाटन के दौरान फाउंडेशन के सदस्यों और विज्ञान शिक्षकों ने बच्चों को नए उपकरणों से कई रोचक प्रयोग भी करवाए। बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय समुदाय ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया। फाउंडेशन करेगा नियमित मॉनिटरिंग ऐसे में कर विद्यालय प्रशासन ने बताया कि विज्ञान किट्स के सुरक्षित, नियमित और दीर्घकालिक उपयोग के लिए फाउंडेशन समय-समय पर मॉनिटरिंग और प्रभाव मूल्यांकन करेगा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का पुष्प मालाएं पहनाकर सम्मान किया। वही सरकारी विद्यालय में विज्ञान शिक्षा का यह स्तर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा।

पानी सप्लायर की पिकअप ने मारी टक्कर छः हुए जख्मी, महिलाओं को लगीं ज्यादा चोट

सादिक हिंदुस्तानी

जयपुर (रॉयल पत्रकार) । पानी सप्लायरों की मनमानी ने जनता को कर रखा है परेशान और सरकार को लगा रहे हैं चूना। मनमाने ढंग से जनता से पैसे वसूलते हैं। जितने भी पानी सप्लाई की गाड़ियां हैं। उनमें से 90 परसेंट गाड़ियों के कागज कंप्लीट नहीं है । अभी हाल ही में लालावास बंधा कचरा डिपो के पास नाई की थड़ी में रोंग साइट चलते हुए एक ई रिक्शा के जबरदस्त टक्कर मार दी जिसमें तीन महिलाएं एक पुरुष और तीन बच्चे ज़ख्मी हो गए थे। जिसमें दो महिला और एक बच्ची के ज्यादा चोंट आई है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जयसिंहपुरा खोर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी महिलाओं को मान बाग हाईवे रोड पर स्थित आशीर्वाद प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर बाद जयसिंहपुर खोर के इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पानी सप्लायर की पिकअप RJ 14 GA 8782 को थाने ले जाकर जब्त कर ली हैं।

बताते हैं कि जख्मी महिलाओं के रिश्तेदारों ने वाटर प्लांट के ओनर विष्णु शर्मा से बात की तो उसने बच्ची का (ऑपरेशन) और महिला का इलाज कराने से मना कर दिया। जब क्लेम करने के बारे में बात और पिक अप के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला है कि यह (पिक अप) गाड़ी कबाड़ी से खरीदी गई है। जिसका न इंश्योरेंस है ना आर सी है ना कागज है। ऐसी और भी गाड़ियां हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है और मनमाने ढंग से चल रही है। सरकार को बगैर टेक्स दिए और बगैर कागज बनवाए, दादागिरी से चल रही है। जिसको ना कोई रोकने वाला है ना कोई ठोकने वाला। अब बेचारी दो महिला है बिस्तर पर पड़ी हुई है ना कोई उनकी सुद ले रहा है। ना कोई मदद कर रहा है। काम करने वाली गरीब महिलाए अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। और आरटीओ कार्यालय के पदाधिकारी क्या एक्शन लेते है। और पीड़ित महिलाओं को क्या मदद दिलवाते हैं या फिर ले-देकर फिर कोई दूसरा एक्सीडेंट करने के लिए, सड़क पर चलने की लिए खुली छूट दे दी जाती हैं। यह नाई की थड़ी की जनता शासन प्रशासन से पूछ रही है सवाल। वरना राजस्थान के न्याय प्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दरबार में अरजी लगाएंगे ।

जयपुर पूर्व पुलिस ने अवैध हरियाणा शराब की बिक्री पर लगाई रोक, 461 बोतल बरामद

जयपुर(रॉयल पत्रिका)। थाना मोती डूंगरी, जयपुर पूर्व ने अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब की बिक्री करने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी सोनू सरदार उर्फ गुरूदीप सिह के किराये के मकान से कुल 461 बोतल अवैध शराब बरामद की। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व, संजीव नैन IPS ने बताया कि आरोपी हरियाणा से शराब चोरी-छिपे लाकर रखता और ऑर्डर मिलने पर बेचता था। गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व और थाना मोती डूंगरी की टीम शामिल रही। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध शराब की जानकारी तुरंत

साझा करें ताकि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

मनोहरपुर की सकरी पुलिया पर बड़ा हादसा

- ट्रेलर में रखी भारी मशीनें गिरीं - चालक के दोनों पैर फ्रैक्चर

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। थाना क्षेत्र की सकरी पुलिया पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। तेज टर्न लेने के दौरान ट्रेलर में लोड भारी मशीनें अचानक चालक पर गिर गईं, जिससे उसके दोनों पैर गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गए। जानकारी अनुसार इस्माइल खान पुत्र सुबराती खान, निवासी नसीराबाद, 18 नवंबर शाम करीब 7:30 बजे ट्रेलर लेकर भिवाड़ी से अजमेर की ओर जा रहा था। ट्रेलर में भारी मशीने भरी हुई थीं। मनोहरपुर की सकरी पुलिया पर मोड़ लेते समय ट्रेलर का संतुलन बिगड़ा और लदी हुई मशीनें सीधे चालक के ऊपर जा गिरीं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेते हुए NHAI की 1033 एंबुलेंस को बुलाया। एंबुलेंस चालक रामू गुर्जर और ईएमटी आकाश शर्मा मौके पर देर किए बिना पहुंचे और गंभीर रूप से घायल चालक को प्राथमिक उपचार देकर निम्स अस्पताल भिजवाया। एंबुलेंस चालक ने बताया कि दुर्घटना में इस्माइल खान के दोनों पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गए हैं और हालत गंभीर बनी हुई है।

आधुनिक संसाधनों से जुडकर विकसित भारत का सपना साकार करें- ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। ग्रामीण विकास, पंचायतीराज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही के राजकीय महाविद्यालय शिवगंज में भामाशाहों के सहयोग से निर्मित ई-लाईब्रेरी का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने भामाशाहों के इस योगदान को अपूर्व और अनुकरणीय बताते हुए उपस्थित युवा शक्ति से आव्हान किया कि अध्ययन में ई-संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए विकसित भारत 2047 अभियान को साकार रूप देने में अपना रचनात्मक योगदान दें। उन्होंनें राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज की विकास योजनाओं की प्रशंसा करते हुए करतल ध्वनि के बीच महाविद्यालय

में 2 नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण विधायक कोष से करने की घोषणा की। उपखण्ड प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सदस्यों, भामाशाहों के परिवार सदस्यों सहित बडी संख्या में विद्यार्थी और नागरिक इस लोकार्पण के साक्षी बने।

44वां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2025:

राजस्थान मंडप में राजस्थानी व्यंजन खूब लुभा रहे है दर्शकों को

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 44वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दर्शकों को राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद राजस्थान मंडप व फूड कोर्ट की ओर खूब ही आकर्षित कर रहा है। राजस्थान मंडप के निदेशक हर्ष शर्मा ने बताया की इस वर्ष राजस्थान मेले में पार्टनर स्टेट की भूमिका निभा रहा है। इसलिए मंडप में हमने राजस्थान की सभी क्षेत्रीय पहचानों को जगह देने की कोशिश की है। मंडप में मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाढ, हाडोती और शेखावाटी के क्षेत्रीय खानपान लोगों को खूब लुभा रहे हैं। राजस्थान की तिल पापड़ी, गजक, बीकानेर के मशहूर पापड़, नमकीन-भुजिया, भेलपुरी, आचार, डिब्बा बंद मिष्ठान, कुल्फी, मुरब्बा, चूर्ण, मसाले, राजजीरा, सूखे मेवा, सूखी सब्जियां और कैर सांगरी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानागर, नागौर, जयपुर, एवं किशनगढ़ आदि विभिन्न अंचलों से आए कारीगरों ने अपने फूड स्टॉल्स पर विभिन्न व्यंजन तैयार कर जनता के समक्ष परोसा। उनके द्वारा बनाए जा रहे पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों दाल-बाटी-चूरमा, बेसन के गट्टे, प्याज की कचैरी, मूंग की दाल की कचैड़ियों, मिर्ची बड़ा, कैर-सांगरी की सब्जी, लहसुन की चटनी से सजी राजस्थानी थाली की खूब बिक्री हो रही है। मंडप में मसालेदार और तीखे स्वाद के साथ ही शर्बत, चटनी, पैक्ड फूड आइटम, गजक, रेवड़ियाँ, चिक्की, हींग, पापड़, एवं पेय पदार्थों में जीरा सोडा इत्यादि आकर्षण का केंद्र रहे। इसी प्रकार प्रदेश के मशहूर हींग और हींग से बने उत्पादों के साथ नींबू चटनी, अथाना मिर्च को भी आगंतुक पसंद कर रहे हैं। राजस्थान के विभिन्न स्टॉलों पर खाद्य-वस्तुओं की उल्लेखनीय बिक्री इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की यह स्वाद-परंपरा आज भी उतनी ही प्रभावशाली और प्रासंगिक है। देश-भर से आए आगंतुकों द्वारा परंपरागत रेसिपी पर आधारित इन उत्पादों को मिली व्यापक सराहना यह दर्शाती है कि राजस्थान न केवल अपने ऐतिहासिक वैभव से बल्कि अपने अनूठे स्वाद और गुणवत्ता से भी पूरे देश को जोड़ने और प्रभावित करने की क्षमता लगातार बनाए हुए है।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए		**पानी के लिए**	
टोल फ्री नंबर	18001806507	जलदाय कार्यालय	2706624
वॉट्सएप नंबर	9414037085	फायर ब्रिगेड	2747400
कस्टमर केयर	2203000	**मेडिकल इमरजेंसी के लिए**	
आईवीआरएस	1912	एंबुलेंस	102/108
कचरा गाड़ी के लिए		एसएमएस इमरजेंसी	2518333
ग्रेटर	2747400	महिला चिकित्सालय	22610616
सीवरेज लीकेज	2607500	जनाना हॉस्पिटल	22378721
हेरिटेज	2607500	SDMH	22574189
टोल फ्री नंबर	14420	SMS ब्लड बैंक	22518222
पुलिस की मदद के लिए		कल्याण ब्लड बैंक	22721771
साइबर क्राइम	1930/2360094	**घायल पशुओं के लिए**	
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	नगर निगम	2747400
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	बर्ड बाइक	9887345580
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	हेल्प इन सफरिंग	8107299711
महिला हेल्पलाइन	1090	जनमंच ट्रस्ट	7230055800
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	पशु चिकित्सालय	2747400

भाजपा ने मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यशाला आयोजित कर दिए निर्देशन

-केबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा रहे उपस्थित

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर की मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR कार्यशाला आज फूल उत्कृष्टता कृषि केंद्र में जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि SIR कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक डॉ. किरोड़ीलाल मीणा उपस्थित रहे, वही विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता के रूप में प्रदेश नेत्री निमिषा गौड मौजूद रही। कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ, कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि SIR प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से त्रुटिरहित करना एवं विश्वशनीय एवं अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो सके। डॉ. किरोड़ी ने कहा कि ये अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाएगा जिसमें हम सभी को सहयोग करना है। मुख्य वक्ता निमिषा गौड एवं जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने भी मतदान गहन पुनरीक्षण अभियान पर अपना मार्गदर्शन दिया और भाजपा द्वारा लगाए गए BLA - 2 और मंडल पदाधिकारियों को इस अभियान में और अधिक सक्रियता करने के लिए कहा। इस दौरान जिला महामंत्री जगदीश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष लालचंद गौतम, हरिओम गर्ग, भाजपा नेता दीपक मीणा, सभापति सुनील तिलकर, पूर्व उपसभापति राजेश गोयल सहित विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष एवं पार्टी के BLA -2 उपस्थित रहे।

किसानों की ट्रैक्टर रैली की सफलता पर सांसद का किया अभिनंदन - मंडेलिया

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में चूरू के युवा लोकप्रिय सांसद राहुल कस्वां का अभिनन्दन व स्वागत कांग्रेसजनों द्वारा किया गया। पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने कहा कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के किसानों की फसल बीमा योजना में लाभान्वित करवाने के राज्य व केन्द्र सरकार से समय समय पर इस मांग को गंभीरता से उठाते हुए और हाल ही में जिले मे ट्रेक्टर रेली का आगाज ही नही अंजाम तक पहुंचाने राजगढ से जयपुर की ओर कुच करते हुए हजारों समर्थकों के साथ ट्रक्टरों के माध्यम से रतनपुरा पहुंचने पर जिला प्रशासन ने अवरोधक लगाकर रोकने का प्रयास किया जिसको जिले की कांग्रेस नेताओं की और किसानों की एकजुटा से उनके मनसुबो को सफल नही होने दिया और सरकार ने जिला प्रशासन के आला अधिकारी जिला कलक्टर और पुलिस अधिक्षक के माध्यम से वार्ता के लिए जयपुर आमंत्रित किया और वार्ता सफल रही। ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नही था। सांसद ने इसकी रूप रेखा बडी बना रखी थी। इसको भांपते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार वार्ता के लिए तैयार हुई और आने वाले दिनों में इसका परिणाम किसानों के हक में देखने को मिलेगा। अपने स्वागत भाषण में राहुल कस्वां ने संबोधित करते हुए कहा कि मै आंदोलन मे सामिल सभी नेताओं व किसानों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनको इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना भरपुर सहयोग देकर इसको अंजाम तक पहुंचाया। यह जीत किसानों की जीत है। एआईसीसी रिहाना रियाज ने कहा कि युवा सांसद होने के साथ साथ राहुल कस्वां संघर्षशील और अनुभवी सांसद है। इनके अनुभव का लाभ पार्टी को समय समय पर मिलता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। इस अवसर पर इस अवसर पर पीसीसी सचिव रियाजत खां, पूर्व सभापति गोविन्द महनसरिया, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धान्धू, पं.स. प्रतिपक्ष नेता धर्मेन्द्र बुडानिया, मोहनलाल आर्य, किसान नेता आदूराम न्यौल, मोहम्मद हुसैन निर्बाण, रमजान खां, कमला पुनियां, आशाराम सैनी, सुनिता कपुरिया, नारायण बालाण, हेमन्त सिहाग, असलम खां मोयल, हर्ष लाम्बा, शेर खां मलखाण, अली मोहम्मद भाटी, सुरेन्द्र ढण्ड, जगनाराम, शरीफ रतननगर, सोहनलाल मेघवाल, लिलाधर चुलेट, सुखाराम घिंटाला, लालाचंद सैनी, रामेश्वर प्रजापत, विधाधर मेघवाल, योगेश ढाका, दीपिका सोनी, ज्योती सिंह, बालीबाई, जयचंद मेघवाल, शिवकुमार शर्मा, सुरेश फोगावट अजीज खा, संजय भाटी, आरिफ रिसालदार, तोफिक खान, समीउल्लाह, जाफर खां, बाबूमंत्री, सलीम पीए, सोयल डीके, तारिख नागौरी, नौमान सयैद, विनोद खटीक, गोकुल शर्मा, अनीस खान, विश्वनाथ सैनी, सहित सैकडों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एमसीएचएन दिवस पर किया गया टीकाकरण

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर जिले में गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर टीके लगाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि गुरुवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सत्रों का आयोजन कर टीकाकरण किया गया। वंचित बच्चों का टीकाकरण कर इसकी प्रविष्टियां यूविन पर दर्ज की गयी। जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। जिले के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों में गुरुवार को एमसीएचएन डे पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। साथ ही टीकाकरण सत्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों को टीकाकृत किया गया। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, टीकाकरण, पोषण, संतुलित आहार, बच्चों का वजन लिया गया, समय पर एएनसी चेकअप करवाने संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव व पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की गई। आयोजित किए गए सत्रों का जिला स्तरीय, खंड स्तरीय अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर ओडीके एप पर इंद्राज भी किया गया। व्यवस्थाऐं जांची गई व अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड संधारण की जांच भी की गई। सत्रों में जिन स्थानों पर कमियां पाई गई उनमें सुधार के निर्देष दिए गए। सभी वैक्सीनेटर्स को प्लान के अनुसार समय पर सम्पूर्ण टीकाकरण करने हेतु पाबन्द किया गया एवं आंगनबाडी केन्द्र पर साफ-सफाई एवं पूरक पोषाहार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियां दी गयी। आषाओं द्वारा की जाने वाली एचबीएनसी विजिट, ड्यू लिस्ट, एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के रजिस्टरों की जांच कर रिकॉर्ड संधारण करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित विशेष अभियान न्याय आपके द्वार- लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान के सफल क्रियान्वयन हेतु देवेन्द्र दीक्षित, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशन में समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर जनउपयोगी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिग, बीमा एवं वित्तीय सेवाओ से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया और महत्व की जानकारी दी। सचिव समीक्षा गौतम ने बताया कि स्थायी लोक अदालतों का गठन जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु किया गया है, जिससे आमजन को जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सौहार्द्रपूर्ण वैकल्पिक समाधान शीघ्रता से प्रदान किया जा सके तथा जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विभागों एवं संस्थानों की न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही प्रस्तुत की जा सकें। वर्तमान समय में शहरीकरण होने तथा सरकारी सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण आमजन की शिकायतों एवं विवादों में वृद्धि हुई है। अतः ऐसी शिकायतों एवं विवादों के शीघ्र व प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान "न्याय आपके द्वार- लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान" प्रारम्भ किया गया है। यह अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक चलाया जायेगा। इस अभियान के तहत अपनी जनउपयोगी शिकायतों को निर्धारित प्रारूप में भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के हेल्पलाइन नंबर 8306002136 या राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के व्हाट्सएप नंबर 9119365734 पर प्रेषित की जा सकती है। इस अभियान के तहत बिना वकील और बिना लंबी कार्यवाही के जनता अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त कर सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याएँ साझा कीं, अधिकार मित्रों मोरसिंह गुर्जर एवं रायसिंह गुर्जर द्वारा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर मौके पर ही कुल 10 आवेदन भरवाएं गए एवं उनसे दस्तावेज प्राप्त किये। इस दौरान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाड़ा हेमंत मेहरा एवं स्थानीय सरपंच ने भी इस अभियान के तहत लोगों से अपनी जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए आवेदन करने की अपील की गई।

हजरत इश्क अली शाह का उर्स शुरू

-22 नवंबर शाम 4:00 बजे होगी कूल की रस्म

जोधपुर (रॉयल पत्रिका)। हजरत इश्क अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक शुरू हो चुका है। मूत्तवली राजू खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के दौरान नियमित रूप से कव्वाली ओर लंगर का आयोजन जायरीनों के लिए किया जाएगा। उर्स की तैयारी को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उर्स के दौरान मोइनुद्दीन मनचला, सलाम मनचला, विक्की मनचला, इकबाल मनचला, दिलशाद मनचला, इरफान तूफेल, शौकत अंन्दाज सूफियाना कलाम पेश करेंगे 22 नवंबर शाम 4:00 बजे कूल की रस्म अदायगी की जायगी। झण्डे की रस्म के मौके पर राजू खान मुत्तवली, मोहम्मद सदीक सेक्रेटरी, मोहम्मद फारूक कोषाध्यक्ष, समाजसेवी साजिद खान जोधाणा, अकबर खान, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद हारून, सरपरस्त मोहम्मद जावेद, आबिद हुसैन, समीर खान, अमजद खान, अनवर हुसैन, वक्फ कमेटी हजरत इश्क अली शाह क तमाम पदाधिकारी व सदस्य सहित कई अकीदतमंद उपस्थित रहे।

बाल अधिकार सप्ताह के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के निर्देशन में चाईल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुतलपुरा, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरवाल, त्रिनेत्र बाल गृह, उच्च माध्यमिक विद्यालय रामड़ी, चौथ का बरवाड़ा में, पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी सवाई माधोपुर एवं रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर पर जाकर बच्चों से जुड़े कानून एवं अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। चाईल्ड हेल्पलाइन कॉर्डिनेटर मुकेश वर्मा के नेतृत्व में बाल अधिकार सप्ताह के अंतर्गत बाल सुरक्षा, बाल विवाह, बाल शोषण एवं बाल श्रम आदि के अनेक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा जानकारी देते हुए समझाया कि सभी छात्र-छात्राओं को यौन शोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है जो लड़की के लिए 18 और लड़के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह को प्रतिबंधित करता हैं। इस दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं और अध्यापकों को बाल-विवाह नहीं करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान मानव तस्करी विरोधी इकाई से सैयद अंसार अली, रेलवे सुरक्षा बल से एएसआई पृथ्वीसिंह मीणा, अर्चना पाठक एवं चाईल्ड हेल्पलाइन टीम से काउंसलर लवली जैन, सुपरवाइजर कपिल स्वर्णकार, हनुमान सैनी, मीना कुमारी, केस वर्कर लोकेश बैरवा, राहुल सिंह और दिलखुश वर्मा मौजूद रहे।

स्थाई लोक अदालतें आम आदमी के लिए आसान न्याय विषेष अभियान

झुंझुनूं (रॉयल पत्रिका)। जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं श्रीमती दीपा गुर्जर तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं महेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा अभिभाषक संघ झुंझुनूं के सभाकक्ष में एलएडीसीएस एवं पैनल के अधिवक्ताओं तथा जिला मुख्यालय के अन्य अधिवक्तागण के साथ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा विधिक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर चलाए जा रहे तीन माह के लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान विषेष अभियान के बारे में चर्चा की व समस्त अधिवक्तागण को इस अभियान हिस्सा बनने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीष द्वारा बताया गया कि लोक उपयोगी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक/षैक्षणिक सेवाएं, आवास एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा आदि से जुड़ी षिकायतों जैसे लंबे समय तक पानी न मिलना, पानी के मीटर/बिल में त्रुटि, दूषित जल की आपूर्ति, बिजली के अत्यधिक बिल, बार-बार बिजली की कटौती, बिजली के नए कनेक्षन में देरी, सरकारी बस या रेल की आत्र के दौरान टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना, सेवा में अनियमितता, यात्रा के दौरान सामान क्षतिग्रस्त होना, सरकारी अस्पताल में उपचार/दवाओं में देरी, आवष्यक सुविधाओं का अभाव, चिकित्सा में गंभीर लापरवाही, नागरिकों के आवास व आस-पास के क्षेत्रों में सीवरेज या सफाई संबंधी समस्याएं, स्ट्रीट लाइट खराब होने, आवास संबंधित अनियमितताएं, बैंकिंग व बीमा के खाता संचालन में गंभीर त्रुटि, ऋण प्रक्रिया में अनुचित विलंब, बीमा दावा समय पर न मिलना, शहरी स्वच्छता, कचरा प्रबंधन आदि से संबंधित आम नागरिकों को आने वाली समस्याओं के समाधान का प्रयास स्थाई लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के सचिव डॉ. महेन्द्र सोलंकी ने बताया कि आमजन को लोक उपयोगिता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए साधारण लिखित आवेदन स्थाई लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए कोई वकील रखने की भी आवष्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के हेल्पलाईन नम्बर 8306002128 पर व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त रालसा के व्हाटसएप नम्बर 9119365734 पर भी प्रेषित की जा सकती हैं। डॉ. सोलंकी द्वारा उपस्थित सभी अधिवक्तागण को यह जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उनको उचित जानकारी देने का आग्रह किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अभिभाषक संघ अधिवक्ता सुभाष चंद्र पूनियां, सचिव अधिवक्ता पवन कुमार, अधिवक्ता नफीस अहमद खान, अधिवक्ता महेष चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता द्वारका प्रसाद वर्मा, अधिवक्ता सुभाष शर्मा, अधिवक्ता उम्मेद राज सैनी, अधिवक्ता उम्मेद सिंह, अधिवक्ता किरण बियाला, अधिवक्ता स्वीटी चौहान, अधिवक्ता बाबूलाल सैनी, अधिवक्ता रामसिंह छापूनियां, अधिवक्ता राजेष बागोरिया, अधिवक्ता अषोक शर्मा व अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहें।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर- 2026 के दौरान बीएलओ राजेंद्र कुमार को प्रशस्ति-पत्र भेंट कर किया सम्मानित

हनुमानगढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने गुरुवार को कलक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी वीसी कक्ष में एसआईआर—2026 के तहत जिले के नोहर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 255 के बीएलओ राजेंद्र कुमार को शत— प्रतिशत कार्य करने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति—पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नोहर ईआरओ राहुल श्रीवास्तव, एपीआरओ राजपाल भी मौजूद रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यादव ने बीएलओ को उल्लेखनीय कार्य के लिए शाबाशी दी और निरंतर दायित्व निर्वहन के साथ परिवेश के लोगों को एसआईआर—2026 के दौरान आवश्यक रूप से गणना प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने सभी बीएलओ को प्रभावी रणनीति से गणना प्रपत्रों के डिजीटाइजेशन कार्य करने हेतु प्रेरित किया है। बीएलओ राजेंद्र कुमार ने कार्य के दौरान अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह 2015 से बीएलओ का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाग के मतदाताओं के रिकॉर्ड को ऑफलाइन रजिस्टर बनाकर दर्ज किया। ईआरओ द्वारा दिए गए समस्त दिशा—निर्देश व एसआईआर—2026 में होने वाले कार्यों की जानकारी मतदाताओं को दी तथा गणना प्रपत्रों के मोहले वाइज बंडल तैयार कर वितरित किए। शुरुआती दिनों में सभी फॉर्म वितरण करने का लक्ष्य रखा तथा पढ़े — लिखे मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना बताया सिखाया, जिससे आधे से अधिक फॉर्म मतदाताओं ने ही पूर्ण कर दिए। इसी के साथ 10 नवंबर से गणना प्रपत्र कलेक्शन का कार्य प्रारंभ कर अगले दिन से डिजिटाइजेशन भी प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं, इसलिए उनसे फॉर्म लेने का कार्य प्रातः काल और सायं काल रखा व दिन के समय फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य किया। इस तरह से लगातार कार्य करते रहने से 19 नवंबर तक शत प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ। बीएलओ राजेंद्र कुमार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी भांभुआन में अध्यापक पद पर कार्यरत है। राजेंद्र कुमार, पूर्व में भी 2 बार (2023 तथा 2024) में सम्मानित हो चुके हैं। 2023 में आधार अपडेशन में उत्कृष्ट कार्य करने एवं 2024 में लोकसभा चुनावों में इनके बूथ पर 88 प्रतिशत मतदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाकिर मंसूरी व एडवोकेट अमीनुद्दीन ने की अमीन पठान से मुलाकात

-अंता उपचुनाव में अमीन पठान ने पारंपरिक अल्पसंख्यक वोटों को कांग्रेस के पक्ष में किया था मजबूत

कोटा (रॉयल पत्रिका)। हाल ही में संपन्न हुए अंता विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वैसे तो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रहे अशोक चांदना को नीचे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बेहतर मैनेजमेंट की बधाई मिल रही है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के वोटों की बात करें तो इनको कांग्रेस के पक्ष में बनाए रखने ओर डोर टू डोर कैंपेन करने में बड़ा योगदान रहा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान का। उन्होंने अंता विधानसभा क्षेत्र के अंता, मांगरोल, सीसवाली, बालाखेड़ा, बालदडा, चहेडिया, पलायथा सहित कई छोटे - बड़े गांव व कस्बों में घर - घर जाकर पूरी क्षमता से कार्य किया। पार्टी से नाराज़ चल रहे कार्यकर्ताओं को मनाया, सभी को साथ लेकर कमान संभाली। जिसका नतीजा रहा कि मुस्लिम समाज के एकमुश्त वोट प्रमोद जैन भाया के पक्ष में पढ़े। ओर प्रमोद जैन भाया ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान को चुनाव में कांग्रेस के प्रति बेहतर मैनेजमेंट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, नव निर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया सहित कई बड़े नेताओं ओर पदाधिकारियों ने बधाई दी। गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जाकिर मंसूरी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अटरु के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अमीनुद्दीन ने कोटा स्थित उनके निजी आवास पर जाकर इस्तकबाल कर मुबारकबाद पेश की।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का देशव्यापी पड़ोसियों के अधिकार अभियान

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान के सह-सचिव मोहम्मद आज़म खान ने "आदर्श पड़ोसी, आदर्श समाज" के नारे के साथ "पड़ोसियों के अधिकारों" को लेकर दस-दिवसीय देश व्यापी मुहिम को सवाई माधोपुर में शुरू करने की घोषणा की है। यह मुहिम 21 से 30 नवंबर 2025 तक पूरे देश में चलेगी, जिसका उद्देश्य पड़ोसियों के प्रति अच्छे व्यवहार और सद्भावना की भावना को फिर से जगाना और सामुदायिक संबंधों को मज़बूत करना है। मीडिया को जारी एक बयान में मोहम्मद आज़म खान ने कहा, "इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों को बड़ा महत्व देता है और इसे एक सामंजस्यपूर्ण समाज की आधारशिला मानता है। कुरआन में अपने अनुयायियों को स्पष्ट रूप से न केवल निकटम पड़ोसियों के साथ, बल्कि 'अस्थाई पड़ोसी' के रूप में निकट आए लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है जिसमें सहकर्मी, सहयात्री और यहाँ तक कि सड़क पर हमारे साथ चलने वाले लोग भी शामिल हैं। इस मुहिम के ज़रिए, हम मुसलमानों को इन अनिवार्य शिक्षाओं की याद दिलाना चाहते हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी बनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि समाज के सामने इस्लाम का सही चेहरा पेश किया जा सके।" मोहम्मद आज़म खान ने कहा, "अच्छे रिश्तों की नींव पर बना समाज अपने आप ही एक मिसाली समाज बन जाता है। जब पड़ोसी एक-दूसरे के साथ दया, क्षमा और इंसाफ़ के साथ पेश आते हैं, तो इससे उठने वाली लहर पूरे समाज को परिवर्तित कर देती है। हमें उम्मीद है कि यह मुहिम न सिर्फ पड़ोसियों के बीच के झगड़े सुलझाएगी, बल्कि दया और सामाजिक ज़िम्मेदारी जैसे इस्लामी मूल्यों का एक मज़बूत सबूत भी बनेगी।" "पड़ोसियों के अधिकार मुहिम" के सवाई माधोपुर संयोजक मुबारक अली ने बताया कि यह मुहिम शहरी इलाकों में बढ़ते अकेलेपन की भावना को सम्बोधित करती है। जिसकी वजह से पड़ोसी रिश्तों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस मुहिम का मकसद आपसी हमदर्दी, सहयोग, साफ़-सफाई और ट्रैफिक डिसिप्लिन को बढ़ावा देना है जिसे इस्लाम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानता है। इस मुहिम में कई तरह कार्यक्रम होंगे, जैसे सभी धर्मो के पड़ोसियों के साथ मीटिंग, चाय सभाएं, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रोग्राम, मोहल्लों में सफाई मुहिम, रास्ते के अधिकारों पर जागरूकता रैलियां, और सांस्कृतिक प्रतियोगताएं। विभिन्न धर्मों के बीच ताल मेल को मज़बूत करने और इस्लाम के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए गैर-मुस्लिम भाइयों और बहनों तक पहुंचने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। इस मुहिम में 'अपने पड़ोसी को जानें', आस-पड़ोस में सांस्कृतिक सभाएं, और स्थानीय समितियों की योजना भी शामिल होंगा ताकि मुहिम के बाद भी लगातार विचार विमर्श और फॉलो-अप को प्रोत्साहन मिलता रहे।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना में घायल महेश चंद मीणा को मिला 1 लाख का चेक

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आमजन के लिए संबल सिद्ध हो रही है। इसी क्रम में सवाई माधोपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सूरवाल निवासी महेश चंद मीणा को योजना के तहत एक लाख रुपये की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। जानकारी के अनुसार महेश चंद मीणा खेत पर काम करते समय 11 हजार केवी लाइन का तार टूटकर उन पर गिर गया, जिससे उनका एक हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सकों को उनका हाथ काटना पड़ा। पीड़ित द्वारा मंडी रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कराया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें यह भुगतान स्वीकृत हुआ।

गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के जिला प्रबंधक प्रदीप द्वारा बीमित महेश चंद मीणा को एक लाख रुपए की बीमा राशि का चेक सौंपा गया। चेक प्राप्त कर महेश चंद मीणा ने संतोष और आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर एलडीएम प्रदीप, सीएफएल सेंटर मैनेजर कल्पना नागर, यूनियन बैंक की उप शाखा प्रबंधक रजनी रावत तथा सहायक प्रबंधक संजय मीणा ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान शाखा के प्रधान खजांची हेमंत महावर भी उपस्थित रहे।

जिले में 4 लाख 60 हजार 996 मतदाताओं की मैपिंग पुरी

-प्रदेश में बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा टॉप 10 में शामिल

धोलपुर (रॉयल पत्रिका)। जिले में मतदाता सूची में गहन विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुल मतदाताओं 9 लाख 17 हजार 846 में से 4 लाख 60 हजार 996 मतदाताओं की मैपिंग अब तक की जा चुकी है, जिसका प्रतिशत 50.23 है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में 60.60 प्रतिशत, परिगणना परिपत्र डिजिटाइन किए जा चुके हैं जिनका राज्य स्तरीय रैंकिंग में दुसरा स्थान है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल मतदाता 9 लाख 17 हजार 846 है, जिनके एसभाईभार कार्य के लिए 942 बीएलओ नियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ के द्वारा परिगणना प्रपत्र डिजिटाइज में सहायता हेतु जिले भर के सूचना सहायक, कंप्यूटर अनुदेशकों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 19 नवम्बर तक कुल मतदाताओं में से विधानसभा क्षेत्र 77-बाड़ी में 1 लाख 23 हजार 28, विधानसभा क्षेत्र 78-बसेड़ी में 1 लाख 49 हजार 897, विधानसभा क्षेत्र 79-धौलपुर में 1 लाख 226 तथा विधानसभा क्षेत्र 80-राजाखेड़ा में 87 हजार 845 कुल 4 लाख 60 हजार 996 मतदाताओं (50.23 प्रतिशत) फार्म डिजिटाइन किए गए है। बीएलओ अभियान में मतदाताओं के घर-घर सर्वे के दौरान 3 बार जा रहा है।

मैपिंग के लिए वेबसाइट पर देख सकेंगे डाटा-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर किसी मतदाता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है तो वह वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपने माता, पिता, दादा, दादी का नाम वर्ष 2025 की मतदाता सूची से मैप करा सकता है। उन्होंने बताया कि विवाहित महिला जिस राज्य की है, वहां अपने माता, पिता, दादा, दादी के नाम से मैप करा सकती है। उन्होंने बताया कि विगत एसआईआर के समस्त राज्य की मतदाता सूची voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

बीएलओ कर रहे हैं अच्छा कार्य-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में बीएलओ अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसके कारण ही 77-बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाग संख्या 75 के बीएलओ अतर सिंह ने 95.14 प्रतिशत, भाग संख्या 81 के बीएलओ वीर सिंह ने 91.10 प्रतिशत, 78-बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाग संख्या 115 के बीएलओ जय सिंह ने 98.64 प्रतिशत, भाग संख्या 156 के बीएलओ संजीव कुमार ने 98.40 प्रतिशत, 79-धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाग संख्या 147 के बीएलओ राजवीर सिंह ने 96.34 प्रतिशत, भाग संख्या 48 के बीएलओ सन्दीप कुमार ने 86.36 प्रतिशत, 80-राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 201 के बीएलओ भूपेन्द्र कुमार ने 90.52 प्रतिशत एवं भाग संख्या 47 के बीएलओ बहादुर सिंह ने 80.65 प्रतिशत परिगणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।

न्याय आपके द्वार ख्यालीवाला में लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में किया जागरूक

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। माननीय रालसा, जयपुर के तत्वावधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान "न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान" के सम्बंध में ग्राम पंचायत ख्यालीवाला भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में बुधवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत ख्यालीवाला के सरपंच मोहन लाल द्वारा जागरूकता शिविर में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। शिविर के दौरान एडीजे सुथार ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा पूरे प्रदेश में लोक उपयोगी समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान के सम्बंध में एक अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिसका उद्देश्य आमजन से सम्बंधित लोक उपयोगी समस्याओं जैसे सड़क, रेल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा, बिजली या पानी की आपूर्ति, लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली अस्पताल या डिसपेंसरी में स्वास्थ्य संबंधी सेवायें, बीमा सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवाएं, एलपीजी सेवा, शैक्षिक अथवा शैक्षणिक संस्थानों तथा आवासीय एवं भू-सम्पदा सेवाओं से सम्बंधित किसी की कोई समस्या हो तो वे प्राधिकरण में व्यक्तिगत उपस्थित होकर या रालसा की वेबसाईट https://rajasthan.nalsa.gov.in से फार्म डाउनलोड कर प्रार्थना पत्र भरकर सीधे ही रालसा के हेल्पलाईन नं. पर 9119365734 पर भिजवा सकते हैं। जन लोक उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित शिकायत या समस्या के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता से अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जायेगा जो पक्षकार की शिकायत या समस्या के निराकरण हेतु जिला स्थाई लोक अदालत श्रीगंगानगर में प्रकरण दायर करेगा, जिसके लिए पक्षकार से कोई शुल्क या फीस नहीं ली जायेगी। इस दौरान चीफ रोहताश यादव द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर के दौरान चीफ एलएडीसी रोहिताश यादव व एलएडीसी अमन चलाना भी उपस्थित रहे।

एसडीआरएफ के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। बूंदी जिले में एसडीआरएफ नोर्म्स के तहत संचालित मरम्मत एवं स्वीकृत कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि एसडीआरएफ नोर्म्स के तहत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर अतिशीघ्र बिल भिजवाएं। उन्होंने विभागवार बिल भिजवाने की समय सीमा निर्धारित की। सभी ब्लॉकों पर संबंधित सीडीपीओ, सीबीईओ के साथ विकास अधिकारी नियमित रूप से एसडीआरएफ कार्यों की समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन करावें, ताकि कार्यों में गुणवत्ता व निर्धारित समय सीमा में मरम्मत कार्य में प्रगति लाई जा सकें। अप्रारंभ कार्य को तत्काल प्रारंभ करवाएं। नियमित रूप से निरीक्षण भी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मरम्मत कार्यों के उपरांत भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट में इस बात का ध्यान रखें कि वास्तविक कार्य और ऑनलाइन फीडिंग किए गए कार्यों में अंतर नहीं आए। जिन कार्यों की टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शीघ्र कार्यादेश जारी कर शुरू करवाया जावें। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग विशेष प्रयास करते हुए समय से कार्य पूर्ण करवाएं। उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता के साथ समझौता करने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एमपी, एमएलए कोष के लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्ण हो चुके कार्यों की सीसी व यूसीसी तत्काल भिजवाएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जावें। श्मशान विकास के कार्यों में चबूतरा, वृक्षारोपण, समतलीकरण, टीनशेड निर्माण के कार्य ही स्वीकृत किए जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिन लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी हैं, उनका प्रथम स्तर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाकर द्वितीय किश्त जारी की जावें। स्वामित्व योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास किए जाएं। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, उप निदेशक आईसीडीएस ऋचा चतुर्वेदी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कुंज बिहारी भारद्वाज, सभी ब्लॉक विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।

बिना लाइसेंस संचालित हो रहे नशा मुक्ति केन्द्र पर जिला प्रशासन की कार्यवाही

-प्रतिबंधित दवाएं मिलने पर नशा मुक्ति केन्द्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

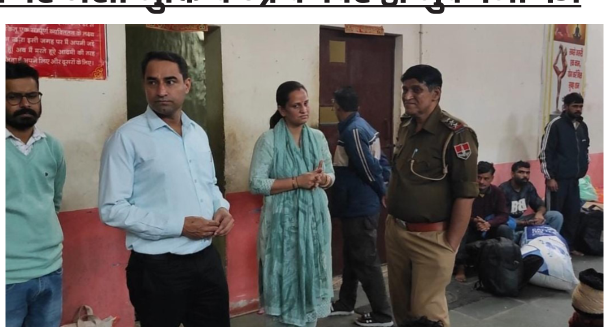

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार नशे की रोकथाम के लिये श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को जिला कलक्टर डॉ. मंजू के निर्देशानुसार सादुलशहर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सादुलशहर क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित हो रहे नशा मुक्ति केन्द्र पर कार्यवाही की गई। मौके पर प्रतिबंधित दवाएं मिलने पर नशा मुक्ति केन्द्र के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विरेन्द्र पाल सिंह सेखो ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशानुसार बुधवार को सादुलशहर क्षेत्र में बिना लाइसेंस संचालित महादेव योग ध्यान मेडिटेशन फाउंडेशन ट्रस्ट पर उपखण्ड अधिकारी रवि कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कार्यवाही की गई। यहां नशा मुक्ति केन्द्र की आड़ में नशा करने की शिकायतें मिली थी। कार्यवाही के दौरान मौके पर 120 रोगी भर्ती पाये गये। नशा मुक्ति केन्द्र पर सुविधाओं का अभाव था और प्रतिबंधित दवाएं भी मिली। इस पर औषधि नियंत्रक निरीक्षक अमनदीप कौर द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सेखो ने बताया कि नशा मुक्ति केन्द्र में मिले रोगियों के परिजनों से संपर्क करने के पश्चात उनकी सहमति से घर भिजवाया गया। आगामी दिवस में शेष रोगियों को घर भिजवाने के पश्चात नशा मुक्ति केन्द्र संचालक को उक्त केन्द्र बंद करने के लिये पाबंद किया गया है। मौके पर संचालक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उनसे भी पूछताछ की गई परन्तु कोई संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई। कार्यवाही के दौरान उपखण्ड अधिकारी और उनके अलावा तहसीलदार, बीसीएमओ, थानाप्रभारी सहित अन्य मौजूद रहे।

बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के तहत छात्र–छात्राओं को दिलाई शपथ

-चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बाल विवाह के दुष्परिणामों की दी जानकारी

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत जिले में ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल के निर्देशन में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा महाराणा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रेमनगर गांधी नगर में बाल विवाह रोकथाम विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र–छात्राओं को बाल विवाह रोकथाम की शपथ दिलाई गई तथा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। टीम ने बच्चों को बताया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने विद्यार्थी एवं विद्यालय स्टाफ को प्रेरित किया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज कराएं। टीम ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। साथ ही यह भी बताया गया कि 0 से 18 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को सहायता की आवश्यकता होने पर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर करण जीनवाल, केस वर्कर सीमा राजोरा, विद्यालय प्राचार्य सविता आमेरिया, तथा शिक्षक लीला चेचानी, विनीता काबरा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार: श्रीगंगानगर के खरलां जल उपयोक्ता संगम को तृतीय पुरस्कार

-जिला कलक्टर ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान के जल संरक्षण और संचयन के कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों-2024 में खरलां जल उपयोक्ता संगम, श्रीगंगानगर ने सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पर जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने जल संसाधन विभाग एवं जल उपयोक्ता संगम खरलां को बधाई व शुभकामनाएं दी है। जल संसाधन विभाग के एसई धीरज चावला ने बताया कि गत दिवस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ जल उपयोक्ता संगम की श्रेणी में तृतीय स्थान पर रही गंगनहर प्रणाली की जल उपयोक्ता संगम खरलां को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानस्वरूप प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद राशि 1 लाख रूपये जल उपयोक्ता संगम खरलां को प्रदान किये गये। पुरस्कार हेतु जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष जसकौर सिंह रमाणा, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता विजय कांटीवाल मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर के खरलां जल उपयोक्ता संगम ने नहरों व खालों की सफाई, लोगों को वसूली कैंप के प्रति जागरूक करना, काश्तकारों के हित में उनको नई तकनीक से अवगत करवाने जैसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इन कार्यों के माध्यम से आमजन में जल के महत्व के प्रति जागरूकता आई है। पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष रमाणा ने जिला कलक्टर डॉ. मंजू और जिला प्रशासन का आभार जताया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया वृद्धाश्रम का निरीक्षण

धोलपुर (रॉयल पत्रिका)। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा हाउसिंग बोर्ड में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठजनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया एवं वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मैनू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्याएं सुनी एवं उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। जिसमें 7 वृद्धजन उपस्थित मिले निरीक्षण के दौरान सचिव ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों से उनके रहन-सहन, भोजन, नाश्ता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की। वृद्धाश्रम के संचालक को निरीक्षण के दौरान कमरों में साफ-सफाई व सर्दी से बचाव के लिए किए गये इंतजाम को देखने के बाद वहाँ आवासित वृद्धजनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की गयी। सभी वृद्धजनों ने वृद्धाश्रम में प्राप्त हो रहीं सुविधा से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को सुधार के लिए वृद्धाश्रम के इंचार्ज को निर्देशित किया गया तो वृद्धाश्रम इंचार्ज ने बताया कि इस वृद्धाश्रम की देखरेख समाज कल्याण विभाग करता है। भामाशाह के जरिये प्रत्येक वृद्धजन को सहायता राशि प्रदान की जाती है। निरीक्षण के दौरान वृद्धश्रम की बिल्डिंग खराब अवस्था में होने के कारण सचिव ने वृद्धाश्रम के प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे सभी बुजुर्गों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वृद्धाश्रम को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करें जिससे सभी बुर्जुग सुरक्षित रह सके। साथ ही इंचार्ज से वृद्धों की पेंशन के बारे में जानकारी ली तो इंचार्ज ने बताया कि दो बुर्जुगों के जनाधार बनावा दिए गए है एवं वृद्धजनों के पेंशन की प्रक्रिया चालू है।

विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 औद्योगिक कॉलोनियों में पहुँची टीम

-शहरी क्षेत्र में लगे मतदाता हेल्प कैम्प

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत जिले में मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ) चित्तौड़गढ़ बीनू देवल ने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की कॉलोनियों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी में निवासरत पात्र मतदाताओं से संवाद कर गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी तथा मौके पर ही उनकी शंकाओं का समाधान किया। ईआरओ देवल ने औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन से भी चर्चा कर कर्मियों को स्वयं के स्तर पर गणना पत्र भरने के लिए प्रेरित करने और बीएलओ को सहयोग उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। ईआरओ देवल ने बताया कि मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिसमें पात्र मतदाताओं का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निवासियों से अपील की कि वे एसआईआर से संबंधित आवश्यक जानकारी बीएलओ को उपलब्ध करवाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रपत्र भरने, नए मतदाता जोड़ने और आवश्यक संशोधनों की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। भदेसर तहसीलदार शिव सिंह चौहान ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा के बूथ संख्या 258, 260,261 263,265,266 मतदाता बूथों का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बड़ीसादड़ी के अंतर्गत उपतहसील देवगढ़ में आने वाले बूथ लेवल अधिकारी एवं सुपरवाइजर की समीक्षा बैठक धमोतर में ली।

शहरी क्षेत्र में मतदाता हेल्प कैम्पों ने बढ़ाई सुविधा-

शहरी क्षेत्र में मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष हेल्प कैम्पों का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा की भाग संख्या 151, 152 और 153 के अंतर्गत सेगवा हाउसिंग बोर्ड, तिलक नगर, वैशाली नगर, शंकरपुरम, रामनगर कच्ची बस्ती, बालाजी नगर सहित अन्य क्षेत्रों के मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने, वर्ष 2002 की मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम खोजने, नए मतदाताओं के पंजीकरण तथा स्वयं के स्तर पर गणना पत्र ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया समझाई गई।

बाल अधिकार सप्ताह के तहत चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

-अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने हस्ताक्षर कर की अभियान की शुरुआत

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। बाल अधिकार सप्ताह 14 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक बाल अधिकारिता विभाग द्वारा मनाया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को बाल अधिकार सप्ताह की गतिविधि में छठे दिवस जिला कलक्टर परिसर में बाल अधिकार सप्ताह के तहत बाल विवाह, बालश्रम, बाल शोषण एवं बाल भिक्षावृत्ति मुक्त हो श्रीगंगानगर इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। जिला कलक्टर डॉ. मंजू के आदेश पर बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई की सहायक निदेशक रेणु खैरवा के निर्देश की पालना में बाल अधिकारों एवं बाल विवाह की रोकथाम को लेकर निरंतर जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी के तहत बुधवार कलक्टर परिसर में अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता रीना छिम्पा ने हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की है। बाल अधिकार सप्ताह के तहत विगत दिवसों में बाल मेले का आयोजन जिसमें बाल विवाह पर चर्चा हुई। बच्चों के सुरक्षित भविष्य हेतु अभिभावकों द्वारा शपथ कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रम हुये हैं। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के अवसर पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जोगेंद्र कौशिक, सदस्य आनन्द मारवाल, डॉ. रामप्रकाश शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक त्रिलोक वर्मा, सुपरवाइजर आयुष मिढ़ा, पंकज एवं किड्स वैली कान्वेंट स्कूल के बच्चें उपस्थित रहे।

हिंडौन में नकली घी के 15 पीपे जब्त

-खाद्य विभाग, डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

हनीस खान

हिंडौन सिटी (रॉयल पत्रिका)। हिंडौन सिटी में पीलूवाली मस्जिद के पास स्थित एक नकली घी बनाने वाले कारखाने पर दबिश दी। टीम ने कारखाने से भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया। कुल 15 पीपे नकली घी बरामद किए गए, जिनके नमूने जांच के लिए भरतपुर भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग, जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय सिंह, डीएसटी के हेड कॉन्स्टेबल देशराज सहित आकाश सोलंकी, धर्मवीर सिंह, अमीर सिंह, पालवेन्द्र सिंह और रवि सिंह शामिल थे। कोतवाली थाना से एएसआई सूरज सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। नकली घी जब्त करने के बाद, अधिकारियों ने कारखाने को सीज कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

8 बीएलओ ने किया सर्वश्रेष्ठ कार्य

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बुधवार 19 नवम्बर को 8 बीएलओ द्वारा जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ज्योति ककवानी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं के परिगणना प्रपत्रों को मतदाताओं को वितरित कर ऑनालईन डिजिटाईड किये जाने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में बीएलओ को मतदाताओं के घर-घर जाकर परिगणना प्रपत्र को भरवाकर डिजिटाईड किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ को प्रोत्साहित किये जाने के लिए प्रतिदिन दो श्रेणीयों में उत्कृष्ट कार्य किए जाने बीएलओ का चयन कर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) लोक बन्धु द्वारा उन्हें प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी में बीएलओ एप्प के माध्यम से सर्वाधिक परिगणना प्रपत्रों को ऑनलाईन डिजिटाईड करने वाले का चयन किया गया है। द्वितीय श्रेणी में बीएलओ के भाग संख्या में सर्वाधिक मतदाताओं द्वारा स्वयं ऑनलाईन परिगणना प्रपत्र भरने वालों का चयन किया गया है। साथ ही प्रत्येक ईआरओ द्वारा भी इस प्रकार बीएलओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गणना पुनरीक्षण के समेकित कार्य की रैकिंग के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ, सुपरवाईजर एवं संबंधित अधिकारी तथा कार्मिक को जिला स्तर पर सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

फिल्म इवेंट

हॉलीवुड

रैपर निकी ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया गंभीर मुद्दा, राष्ट्रपति ट्रंप को कहा शुक्रिया

रैपर निकी मिनाज संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में नाइजीरिया के ईसाइयों से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाया है। साथ ही इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सराहा है। दरअसल, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नाइजीरिया में ईसाइयों को सताया जा रहा है। इस बात को निकी मिनाज ने भी संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में कहा है। त्रिनिदाद में जन्मी निकी मिनाज ने ट्रंप को शुक्रिया भी कहा क्योंकि इतने जरूरी मुद्दे पर उन्होंने बात की। इस महीने शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों को सताए जाने का मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने यह बात कही, जिस पर निकी मिनाज ने भी रिएक्शन दिया था। इस मुद्दे के चर्चा में आने के बाद संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें निकी ने अमेरिकी मिशन के एक पैनल में अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्ज और रिलीजियस लीडर के साथ बात की। वह कहती हैं, 'दुख की बात है कि यह समस्या न केवल नाइजीरिया में बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों में भी बढ़ती जा रही है।' मिनाज ने कहा कि वह यह बात साफ करना चाहती थीं कि नाइजीरिया में ईसाइयों की रक्षा का मतलब किसी का पक्ष लेना या लोगों को बांटना नहीं है। वह कहती हैं, 'यह लोगों को एकजुट करने के बारे में है।' उन्होंने नाइजीरिया को गहरी आस्था और परंपराओं वाला एक खूबसूरत देश बताया, जिसे देखने के लिए वह बेताब हैं। निकी मिनाज ने आगे कहा, 'धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम सभी अपने धर्म का पालन कर सके, चाहे हम कोई भी हों, हम कहीं भी रहते हों और हमारी आस्था कुछ भी हो।'

टॉलीवुड

अभिनेत्री तुलसी ने फिल्मों को कहा अलविदा इंस्टाग्राम पोस्ट में सभी को बोला- 'थैंक्यू'

साउथ की दिग्गज अभिनेत्री तुलसी ने फिल्मों से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट के जरिए अपने लगभग छह दशक लंबे करियर पर विराम लगाने की जानकारी दी है। तुलसी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। अब उनके फिल्मों से रिटायरमेंट के एलान ने उनके प्रशंसकों को निराश कर दिया है। हालिया वर्षों में अपनी मां की भूमिकाओं के लिए मशहूर तुलसी ने सबसे पहले साईं बाबा के चरणों की एक तस्वीर वाली एक आध्यात्मिक पोस्ट के साथ अपने फैसले की ओर इशारा दिया। साथ में कैप्शन में लिखा था, 'मेरी और मेरे बेटे साईं की रक्षा और मार्गदर्शन करो। हे देवा हे साईंनाथ।' इसके तुरंत बाद एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपको किसी को अपनी भावनाओं को समझाने या उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें; यह सबसे अच्छा जानता है।'तुलसी ने आखिरकार एक और पोस्ट में अपने रिटायरमेंट का साफतौर पर एलान किया। उन्होंने लिखा, 'इस 31 दिसंबर को शिरडी दर्शन के क्रम में मैं अपने लिए रिटायरमेंट की कामना करती हूं और साईंनाथ के साथ शांतिपूर्वक अपनी यात्रा जारी रखूंगी। मैं जीवन को साईराम सीखने में मेरी मदद करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं।' तुलसी ने 1967 की तेलुगु फिल्म 'भार्या' से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बाल कलाकार के रूप में उनका आधिकारिक करियर 1973 में के. बालाचंदर की फिल्म 'अरंगेत्रम' से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों 'सीतामलक्ष्मी' (1978), 'शंकरभरणम' (1979) और 'मुद्दा मंदरम' (1981) शामिल हैं। अपने बाद के करियर में तुलसी सहायक भूमिकाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाने लगीं और उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, मोहनलाल, चिरंजीवी और विजय सेतुपति जैसे दिग्गजों के साथ काम किया।

भोजपुरी

'यूपी वाली बिहार वाली' फिल्म के सेट पर रानी के साथ हुआ प्रैंक, अचानक चीख उठीं एक्ट्रेस

अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'यूपी वाली बिहार वाली' की शूटिंग में बिजी हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रानी की को-स्टार उनके साथ प्रैंक करती दिख रही है।

भोजपुरी अदाकारा रानी चटर्जी का पर्दे पर रौबदार अंदाज नजर आता है। वे पुलिस वाले की भूमिका अदा करें या बहू के रोल में नजर आएं, दमदार आवाज से दिल जीत लेती हैं। मगर, असल जिंदगी में वे ऐसी हैं कि एक खरगोश देखकर भी डर से चीख उठीं। उनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल है। चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री संजना पांडे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। दोनों एक्ट्रेस फिल्म के सेट पर हैं। संजना अपनी साड़ी के पल्लू में एक खरगोश के बच्चे को छिपाकर रानी के पास जाती हैं। रानी के सामने अचानक खरगोश के बच्चे को दिखाते हैं। देखकर रानी अचानक चिल्लाने लगती हैं और छिपने की कोशिश करती हैं। वीडियो के साथ संजना ने कैप्शन लिखा है, 'कभी कभी सेट पर मैं प्रैंक कर देती हूं। 'यूपी वाली बिहार वाली' के सेट पर मैंने खूबसूरत रानी चटर्जी को डरा दिया'। संजना के पोस्ट पर रानी ने कमेंट किया है, 'बदमाश लड़की'। इसके अलावा एक अन्य वीडियो खुद रानी चटर्जी ने शेयर किया है। इसमें वे पेड़ से आंवले तोड़कर खाती नजर आ रही हैं। रानी चटर्जी की फिल्म की शूटिंग किसी गांव में हो रही है।

लाइफ स्टाइल

टॉप ट्रेंड्स

लैक्मे फैशन वीक आधिकारिक तौर पर भले ही समाप्त हो गया है लेकिन इस सीज़न के टॉप ट्रेंड्स चर्चा में है।दरअसल, इस सीज़न में बालों की स्टाइल ने दर्शकों का अपनी ओर ज्यादा ध्यान खींचा। दर्शकों ने इसका भरपूर आनंद भी लिया। कुछ बेहद शानदार हेयरस्टाइल के साथ ढेर सारी हेयर एक्सेसरीज़ भी थीं। इनमें बालों को फूलों, रिबन, हेडगियर, कैप, स्कार्फ और यहाँ तक कि ब्रोच जैसे आभूषणों से सजाया गया था।

बालों को लंबा और घना बनाने में मददगार है आंवला

बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए आंवला का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। इसमें विटामिन सी, आयरन, और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं, जिससे बाल घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं। दरअसल, आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट्स और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिस वजह से ये बालों के लिए काफी लाभदायक होता है। ऐसे में यदि इसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बाल आंतरिक रूप से मजबूत बन सकते हैं।

आंवला तेल से बालों की मालिश

आप चाहें तो आंवला तेल बनाकर आप इससे बालों की मलिश कर सकते हैं। तेल बनाने के लिए सबसे पहले सूखे आंवले के टुकड़े लें और इन्हें नारियल या सरसों के तेल में उबालें। जब तेल का रंग गहरा हो जाए, तो इसे ठंडा करके छान लें। अब इस तेल को ठंडा करके आप हफ्ते में दो बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का तेल बालों को जड़ से मजबूत पहुंचाता है। इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है।

आंवला पाउडर और दही का हेयर मास्क

इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 2-3 चम्मच आंवला पाउडर लें और उसमें पर्याप्त मात्रा में दही मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस मिश्रण को बालों की जड़ों और सिरों पर लगाएं। मास्क को 30-40 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। आंवला और दही का मास्क बालों को पोषण देता है, ड्रायनेस कम करता है और बालों को घना बनाता है। ये मास्क सर्दियों में बालों को मजबूत बनाता है।

आंवला और मेथी का हेयर पैक

इस हेयर पैक को तैयार करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच मेथी पाउडर को पानी में भिगोकर रातभर छोड़ दें। सुबह उठकर इसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को बालों में जड़ों से सिरे तक लगाएं और 30 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। आंवला और मेथी दोनों बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं, बालों को घना बनाते हैं और बालों की मजबूती में सुधार करते हैं।

सर्दियों में साड़ी पहनते समय अपनाएं ट्रिक्स, नहीं लगेगी ठंड

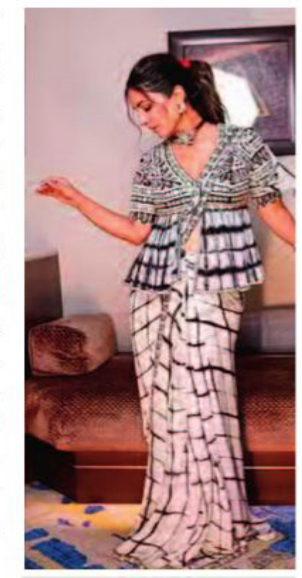

सर्दियां शुरू हो गयी है। सर्दियां लगभग सबको पसंद होती है। इस मौसम में शादी पार्टी का मज़ा ही कुछ और होता है लेकिन ज्यादा ठंड महिलाओं के लिए मुसीबत बन जाती हैं क्योंकि सर्दी के मौसम में महिलाएं शादी के मौके पर खुद को स्टाइल नहीं कर पातीं। दरअसल, महिलाएं महंगे और स्टाइलिश एथनिक या पार्टी वियर कपड़े पहनती हैं लेकिन ठंड बढ़ने के कारण उन्हें स्वेटर या कोट आदि को ऊपर से कैरी करना पड़ता है। ऐसे में उनकी खूबसूरत ड्रेस स्वेटर के नीचे छिप जाती है। इसके अलावा अगर वह विंटर वियर नहीं पहनती तो ठंड और ठिठुरन से परेशान रहती हैं। ऐसे में सारा फैशन बेकार हो जाता है। इसलिए सर्दियों में किसी कार्यक्रम पर साड़ी पहनने वाली महिलाओं को फैशन के मामले में सबसे अधिक परेशानी होती है। आपको सर्दियों में शादी सीजन के लिए कुछ ऐसे टिप्स के जरूर जानना चाहिए, जिसे आजमा कर आप साड़ी को स्टाइलिश तरीके से कैरी कर सकती हैं और आपको ठंड से भी बच सकती हैं।

साड़ी के फैब्रिक का चयन

सर्दी के मौसम में साड़ी पहन रही हैं तो ऐसा फैब्रिक चुने तो मोटा हो। जैसे आप वेलवेट के कपड़े की साड़ी पहन सकती हैं। इस तरह की साड़ियां ठंड से बचाने में आपकी मदद करती हैं और लुक भी अच्छा दिखता है।

फुल स्लीव्स ब्लाउज पहनें

ठंड से बचने के लिए आप ब्लाउज स्टाइल का चयन करते समय ध्यान रखें कि ब्लाउज फुल स्लीव्स के हों। फुल स्लीव्स ब्लाउज फैशन के मुताबिक भी ट्रेंड में हैं। कई मौकों पर अभिनेत्रियों को पूरे बाजू वाले ब्लाउज में देखा जा चुका है।

लांग ब्लाउज कैरी करें

साड़ी के साथ लॉन्ग ब्लाउज भी पहन सकती हैं। लॉन्ग ब्लाउज का फैशन हमेशा रहता है। इस तरह के ब्लाउज के नीचे आप इनर या बॉडी वार्मर पहन सकती हैं।

इंडो वेस्टर्न साड़ी पहने

सर्दी के मौसम में आप इंडो वेस्टर्न साड़ी कैरी कर सकती हैं। ये एथनिक लुक को मॉडर्न टच देने के साथ ही ठंड से भी बचाएंगी।

ऑयली स्किन के लिए रामबाण है बेसन और नीम, ऐसे करें

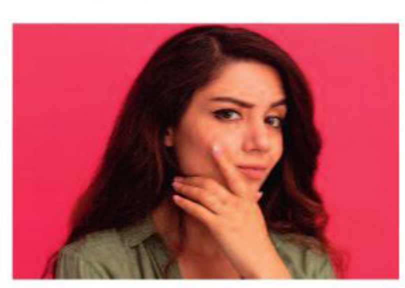

अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप उसकी नेचुरल तरीके से केयर करना चाहती हैं तो ऐसे में आप बेसन और नीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दोनों इंग्रीडिएंट ऑयली स्किन के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं।

नीम और बेसन से बनाएं स्क्रब

अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से एक्सफोलिएट करने के लिए आप नीम और बेसन की मदद से स्क्रब बनाकर इस्तेमाल करें।

स्क्रब बनाने का तरीका-

सबसे पहले, नीम पाउडर, हल्दी और बेसन को मिक्स करें।अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गुलाब जल मिलाएं और फिर पेस्ट बना लें। तैयार मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर सर्कुलर मोशन में रगड़ें।अंत में, गुनगुने पानी से धो लें और फिर स्किन को मॉइश्चराइज करें।

बेसन और नीम से बनाएं फेस मास्क

यह फेस मास्क अतिरिक्त ऑयल को कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। साथ ही साथ, इससे आपके चेहरे पर ग्लो भी आता है।

फेस मास्क बनाने का तरीका-

बेसन, नीम पाउडर और शहद को मिलाकर पेस्ट बना लें।तैयार पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दें।अंत में, फिर गुनगुने पानी से धोकर स्किन को मॉइश्चराइज करें।

नीम और बेसन से बनाएं नाइट क्लींजर

रात को सोने से पहले स्किन को साफ करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप नीम और बेसन की मदद से नाइट क्लींजर बनाएं।

दांतों का पीलापन दूर कीजिए घरेलू नुस्खे से, होगा फायदा

पीले दांत न केवल आपकी खूबसूरती को प्रभावित करते हैं बल्कि आपकी आत्मविश्वास में भी कमी ला सकते हैं। दांतों को सफेद और चमकदार बनाने के लिए आप बहुत से घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं।

बेकिंग सोडा और नींबू

इसके इस्तेमाल के लिए 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाएं। अब इसे टूथब्रश पर लगाकर दांतों पर हल्के हाथों से रगड़ें। दो मिनट के बाद कुल्ला कर लें। आप इसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं।

नारियल तेल

ऑयल पुलिंग की मदद से भी आप अपने दांत साफ कर सकते हैं। इसके लिए 1-2 चम्मच नारियल तेल को मुंह में रख लें। इसके बाद 10-15 मिनट तक इसे मुंह में घुमाएं। इसके बाद कुल्ला करें और फिर ब्रश करें। इससे आपका मुंह भी साफ होगा।

हल्दी और नारियल तेल का मिश्रण

इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं। अब इस पेस्ट को ब्रश की मदद से दांतों पर लगाएं। दो मिनट के बाद कुल्ला कर लें। इससे भी दांतों का पीलापन कम होता है और ये मुंह के बैक्टीरिया को भी खत्म करता है।

सेब का सिरका

इसका इस्तेमाल करना भी काफी सरल है। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले 1 चम्मच सेब के सिरके को पानी में मिलाएं। इससे दिन में एक बार कुल्ला करें। ये दांतों के दाग-धब्बे भी दूर करता है।

कार्नर न्यूज

मेंस फैशन में पारंपरिक और मॉडर्न लुक दोनों ही ठीक

दिखना है स्मार्ट और स्टालिश तो खुद को ऐसे करें तैयार, नजरें टिकी रहेंगी आप पर

किसी भी त्यौहार या शादियों के मौके पर खुद को परफेक्ट लुक देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी होता है। इन मौकों पर मेंस फैशन में पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह के कपड़े अच्छे होते हैं। इन मौकों पर कुर्ता-पायजामा को सबसे अधिक पहना जाता है। यह एक पारंपरिक और आरामदायक विकल्प है। रंग-बिरंगे कुर्ते और कढ़ाई वाले पायजामे अच्छे लगते हैं।

स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या करें

महिलाओं की तरह पुरुष भी अक्सर त्योहारों के दौरान स्टाइलिश तरीके से अलग दिखने के तरीके खोजते हैं। ज्यादातर त्योहारों के दौरान महिलाओं के पहनावे पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। ऐसे में पुरुषों के फैशन को अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि, इस अवसर पर पुरुषों द्वारा कुछ खास स्टाइल अपनाने से उनका रूप-रंग बदल सकता है, जिससे वे स्मार्ट और अट्रैक्टिव दोनों दिख सकते हैं।

नेहरू जैकेट है बेहतर आप्शन

नेहरू जैकेट के साथ कुर्ता पहनने से एक पॉलिश और अट्रैक्टिव लुक मिलता है। नेहरू जैकेट भारतीय पोशाक का एक अहम हिस्सा है। कुर्ते में हल्के रंगों का चयन करना और उन्हें नीले, हरे या भूरे जैसे रंगों में गहरे नेहरू जैकेट के साथ पूरक करना एक ऐसा लुक तैयार कर सकता है जो क्लासी और ऑन-ट्रेंड दोनों होता है।

कढ़ाई की खूबसूरती को अपनाएं

जिन लोगों को डिजाइन पसंद है, उनके लिए कढ़ाई वाले कुर्ते एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन कुर्तों पर किया गया विशेष काम परंपरा का मिश्रण लाता है, जो दीवाली समारोहों के लिए आदर्श है। कढ़ाई वाले कुर्ते का चयन करके पुरुष त्यौहार की थीम के अनुरूप रहते हुए अपना फैशनेबल रूप दिखा सकते हैं।

शेरवानी और डिजाइनर जैकेट

अगर आप थोड़े अधिक फॉर्मल लुक में जाना चाहते हैं, तो शेरवानी पहन सकते हैं। यह खास अवसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुर्ते के ऊपर एक अच्छा सा डिजाइनर जैकेट भी पहन सकते हैं। यह लुक को और भी स्टाइलिश बना देता है।

परंपरा और फैशन के बीच संतुलन बनाना जरूरी

त्यौहार और शादियां ऐसे मौके होते हैं जब हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छे रूप में दिखना चाहता है। पुरुषों के लिए इसका मतलब है परंपरा और मौजूदा फैशन के बीच सही संतुलन बनाना ताकि एक ऐसा लुक तैयार किया जा सके जो स्टाइलिश और अनोखा दोनों हो।

कुराकाओ ने विश्व कप में जगह बनाकर दुनिया को चौंकाया

डेढ़ लाख की आबादी वाले कुराकाओ ने किया कमाल, 12 अंकों के साथ ग्रुप-बी में रहा शीर्ष पर

एजेंसी ▶▶| किंग्सटन

कुराकाओ की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है लेकिन इसके बावजूद उसने अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाकर नया इतिहास रच दिया। कुराकाओ ने जमैका के साथ गोलरहित ड्रॉ खेलकर पहली बार विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। इस तरह से वह फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाने वाला सबसे कम आबादी वाला देश बन गया है। कुराकाओ के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार पिछली जनवरी तक देश की जनसंख्या 156,115 थी। इससे पहले विश्व कप फुटबॉल में जगह बनाने वाला सबसे कम आबादी वाला देश आइसलैंड था। उसने जब 2018 में रूस ने खेले गए विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था तब उसकी जनसंख्या लगभग 350,000 थी।

कोच एडवोकाट के नहीं रहने के बावजूद किया प्रवेश

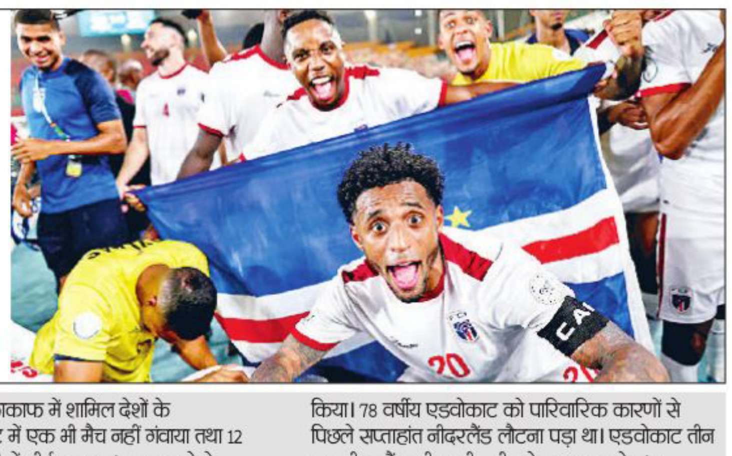

कुराकाओ ने कॉनकाकाफ में शामिल देशों के क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया तथा 12 अंकों के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर रहा। कुराकाओ ने नीदरलैंड के रहने वाले अपने कोच डिक एडवोकाट की अनुपस्थिति के बावजूद यह ऐतिहासिक परिणाम हासिल किया। 78 वर्षीय एडवोकाट को पारिवारिक कारणों से पिछले सप्ताहांत नीदरलैंड लौटना पड़ा था। एडवोकाट तीन बार नीदरलैंड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान रहे तथा कुराकाओ में कार्यभार संभालने से पहले वह दक्षिण कोरिया, बेल्जियम और रूस के कोच रहे थे।

स्कॉटलैंड ने किया 28 साल का सूखा खत्म, किया क्वालीफाई

एजेंसी ▶▶| ग्लासगो

स्कॉटलैंड ने डेनमार्क को हराकर 28 साल के इंतजार के बाद विश्व का फुटबॉल में अपनी जगह सुरक्षित की जबकि ऑस्ट्रिया भी 1998 के बाद पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहा। स्पेन ने यूरोप में प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में 31 मैच तक अजेय रहने के इटली के रिकॉर्ड की बराबरी करके अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाले विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित की। यूरोपीय क्वालीफाइंग समाप्त होने के साथ ही बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड ने भी विश्व कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस तरह से यूरोप से 12 टीमों ने अपने ग्रुप में विजेता बनकर विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

स्विट्जरलैंड ने कोसोवो को हराकर बनाई जगह

स्कॉटलैंड ने ग्रुप सी में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे डेनमार्क को 4-2 से पराजित करके शीर्ष स्थान हासिल किया। डेनमार्क को ग्रुप सी का विजेता बनने के लिए इस मैच में केवल ड्रॉ की जरूरत थी। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर ग्रुप एच में शीर्ष स्थान हासिल करके 28 साल के इंतजार के बाद विश्व कप में वापसी की, जबकि बेल्जियम ने लिचटेंस्टाइन को 7-0 से हराया। स्विट्जरलैंड ने कोसोवो के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलकर विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। मिकेल ओयारजाबल ने 62वें मिनट में बराबरी का गोल दागा, जिससे स्पेन ने घरेलू मैदान पर तुर्किए के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस तरह स्पेन का यूरोप में अजेय रहने का सिलसिला 31 मैचों तक पहुंच गया।

खबर संक्षेप

दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी जाएंगे गिल

नई दिल्ली। कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुवाहाटी जाएंगे। कोलकाता में

खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 26 वर्षीय गिल की गर्दन में अकड़न आ गई थी। वह पहली पारी में चार रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इसके बाद मैच में आगे नहीं खेल पाए थे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'शुभमन पर उपचार पर अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे।'

एनजेडसी के नए अध्यक्ष बने ग्रेटबैच

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी, कोच और चयनकर्ता मार्क ग्रेटबैच को न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) का

नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यूजीलैंड के लिए 1988 से 1996 के बीच 41 टेस्ट और 84 एकदिवसीय मैच खेलने वाले ग्रेटबैच लेस्ली मर्डोक की जगह लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बोर्ड की चेयरमैन डायना पुकेटापु-लिंडन ने कहा, 'मैं पिछले तीन वर्षों में एनजेडसी अध्यक्ष के रूप में लेस्ली के पेशेवर रवैए और खेल के साथ-साथ संगठन के प्रति उनके अपार समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं।'

खेल साहित्य महोत्सव में शिरकत करेंगे सोटोमायोर

नई दिल्ली। क्यूबा के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्डधारी खिलाड़ी जेवियर सोटोमायोर 22 नवंबर को एकाम्र खेल साहित्य महोत्सव (ईएसएलएफ) के सातवें सत्र में मुख्य आकर्षण होंगे। सोटोमायोर ने 1989 में पहली बार ऊंची कूद में आठ फीट की बाधा को पार किया था और 1993 में 2.45 मीटर (आठ फीट 1.4 इंच) का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उनके साथ पैनल में भारत के वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर भी शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु पर बनाई बढ़त : रिंकू ने खेली कॅरियर की सर्वश्रेष्ठ पारी

रेड बॉल में रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी, तमिलनाडु के खिलाफ ठोके 176 रन, जड़ा लगातार दूसरा शतक

एजेंसी ▶▶| कोयंबटूर

टी20 क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका के लिए मशहूर रिंकू सिंह ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कॅरियर की सर्वश्रेष्ठ 176 रन की पारी खेली, जिससे उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए के मैच के चौथे और अंतिम दिन तमिलनाडु के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल करके तीन अंक जुटाए। तमिलनाडु के पहली पारी के 455 रन के जवाब में उत्तर प्रदेश ने 460 रन बनाकर ड्रॉ हुए मैच में तीन अंक हासिल किए। तमिलनाडु को एक अंक मिला। उत्तर प्रदेश को बढ़त दिलाने में रिंकू की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 247 गेंद की अपनी पारी में 17 चौके और छह छक्के मारे।

इस टूर्नामेंट में यह उनका लगातार दूसरा शतक है। पिछले मैच में रिंकू ने आंध्र प्रदेश के खलिाफ 165 रन की पारी खेली थी। भारत की राष्ट्रीय टीम जब स्वदेश में टेस्ट मैच में स्पिनरों का सामना करने में जूझ रही है तब रिंकू ने इस पारी से टीम में जगह बनाने की अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

विदर्भ ने बड़ौदा को 144 रन से हराया

नागपुर में पूर्व चैंपियन विदर्भ ने तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे (15 रन पर पांच विकेट) के कॅरियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से बड़ौदा को 144 रन से हराया। विदर्भ को इस जीत से छह अंक मिले, जिससे उसने तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत की। विदर्भ के 276 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ौदा ने 73 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे और अंततः उसकी पूरी टीम 50.4 ओवर में 131 रन पर सिमट गई। विदर्भ के पहली पारी के 169 रन के जवाब में बड़ौदा ने 166 रन बनाए थे। विदर्भ की जीत में नालकंडे की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण के सात साल बाद पहली बार पारी में पांच विकेट चटकाए। बड़ौदा की ओर से दूसरी पारी में सुकीर्त पांडे 37 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे।

झारखंड ने आंध्र को पारी और 81 रन से दी मात

झारखंड के 328 रन के जवाब में आंध्र ने पहली पारी छह विकेट पर 567 रन बनाकर घोषित की। इसके बाद झारखंड की टीम दूसरी पारी में 158 रन पर सिमट गई और उसे पारी के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। आंध्र की ओर से सौरभ कुमार ने 47 रन पर पांच जबकि त्रिपुराना विजय ने 39 रन पर तीन विकेट चटकाए। आंध्र को इस जीत से बोनस अंक सहित सात अंक मिले।

ओडिशा की नगालैंड पर शानदार जीत

ओडिशा के 465 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नगालैंड की टीम गोविंदा पोद्दार (69 रन पर पांच विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 165 रन पर सिमट गई। नगालैंड की ओर से देगा निश्चल ने सर्वाधिक 52 रन बनाए। ओडिशा को जीत दर्ज करने के लिए छह अंक मिले।

मुंबई ने पुडुचेरी को पारी और 222 रन से हराया

मुंबई। मुंबई ने सिर्फ आधे घंटे में जीत की औपचारिकता पूरी की तथा पुडुचेरी को पारी और 222 रन से हराकर ग्रुप डी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पहली पारी में 498 रन के विशाल अंतर से पीछे रहने वाले पुडुचेरी ने चौथे दिन सुबह 8.3 ओवर में अपने बाकी बचे चार विकेट खोकर केवल 45 रन जोड़े और इस तरह से उसकी पूरी टीम दूसरी पारी में 276 रन पर आउट हो गई। पुडुचेरी की टीम ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 231 रन से की और उसकी हार तय लग रही थी। मुंबई की तरफ से चौथे दिन तुषार देशपांडे ने दो विकेट लिए, जबकि कप्तान शार्दुल ठाकुर और आयुष म्हात्रे को एक-एक विकेट मिला, जिससे मुंबई ने जल्दी ही जीत की औपचारिकता पूरी कर ली। देशपांडे और ठाकुर दोनों ने पांच-पांच विकेट लेकर मैच का अंत किया, जबकि सिद्धेश लाड और आकाश आनंद ने शतक बनाए, जिससे मुंबई ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 630 रन बनाकर पारी घोषित की। पुडुचेरी की टीम पहली पारी में 132 रन ही बना पाई थी। मुंबई ने अपनी तीसरी जीत से सात अंक जुटाए जबकि पुडुचेरी को कोई अंक नहीं मिला।

आईसीसी वनडे रैंकिंग

मिचेल बने दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज, रोहित को पछाड़ा

एजेंसी ▶▶| दुबई

रोहित शर्मा कुछ समय तक शीर्ष पर रहने के बाद जारी आईसीसी की एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक गए जबकि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक की बदौलत मिचेल एकदिवसीय बल्लेबाजों की सूची में नंबर एक स्थान हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने कैरेबियाई टीम के खिलाफ श्रृंखला के शुरुआती मैच में अपना सातवां एकदिवसीय शतक लगाया और यह फॉर्म में चल रहे इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए रोहित को पछाड़कर अपने कॅरियर में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। मिचेल के वर्तमान में 782 रेटिंग अंक हैं, जो रोहित से एक अंक अधिक है। रोहित लगभग तीन हफ्ते तक शीर्ष पर रहे। मिचेल एकदिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज ग्लेन टर्नर 1979 में शीर्ष पर थे।

पहली बार शीर्ष पांच में पहुंचे बावुमा

कोलकाता में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट के समापन के बाद दोनों टीम के कई खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में सुधार हुआ है। मैच की दूसरी पारी में 55 रन बनाकर नाबाद रहे दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा अपने कॅरियर में पहली बार शीर्ष पांच में पहुंच गए हैं। इसी मैच के दौरान चोटिल होने के बावजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल दो स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंटो सिलहट में आयरलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगाने के बाद चार स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीते 11 पदक

बधिर ओलंपिक : अभिनव और प्रांजलि की जोड़ी ने साधा गोल्ड पर निशाना

एजेंसी ▶▶| टोकियो

अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने बधिर ओलंपिक की निशानेबाजी प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि कुशाग्र सिंह राजावत ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया।

इस तरह भारतीय निशानेबाजों ने 25वें बधिर ओलंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारतीय निशानेबाज अभी तक इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीत चुके हैं। अभिनव और प्रांजलि ने चीनी ताइपे के या-जू काओ और मिंग-जुई ह्सू पर 16-6 से शानदार जीत दर्ज कर शीर्ष स्थान हासिल किया।

कुशाग्र ने जीता कांस्य पदक

दूसरी स्पर्धा में कुशाग्र ने 224.3 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। यूक्रेन के दिमित्रो पेट्रेंको ने 251.0 अंक बनाकर बधिर विश्व और ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी के कोलिन म्यूएलर ने 245.4 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया। अभिनव और प्रांजलि ने स्वर्ण पदक के मुकाबले में शुरू से ही अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी और अपने प्रतिद्वंद्वियों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इससे पहले इस जोड़ी ने क्वालीफिकेशन में खुद के ही बधिर विश्व और ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की थी। भारतीय जोड़ी ने कुल मिलाकर 569 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिनव ने 287 और प्राजंलि ने 582 अंक का योगदान दिया। इन दोनों ने क्वालीफिकेशन में भी पहला स्थान हासिल किया था।

15 जनवरी से अंडर 19 विश्व कप, अमेरिका से भारत का पहला मुकाबला

दुबई। भारतीय टीम जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक होने वाले पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप के पहले मैच में अमेरिका से खेलेगी। टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें चार-चार के चार समूहों में बांटा गया है। इसमें 23 दिन के भीतर 41 मैच खेले जाएंगे। भारत को ग्रुप ए में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप बी में जिम्बाब्वे , पाकिस्तान , इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हैं जबकि ग्रुप सी में गत चैंपियन आस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका होंगे। चौथे और आखिरी ग्रुप डी में तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका होंगे। आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की । इस टूर्नामेंट के जरिए तंजानिया पदार्पण करेगा जबकि जापान की 2020 के बाद वापसी होगी। भारत को 15 जनवरी को अमेरिका से खेलना है। इसके बाद 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से खेलना है।

डेविस कप

बेल्जियम ने 10 बार के चैंपियन फ्रांस को हराया, सेमीफाइनल में की जगह पक्की

एजेंसी ▶▶| बोलोग्ना

जिजोउ बर्ग्स ने आर्थर रिंडरक्नेच को 6-3, 7-6 (4) से पराजित किया, जिससे बेल्जियम ने 10 बार के चैंपियन फ्रांस पर 2-0 की जीत के साथ डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। बेल्जियम को फ्रांस के साथ अपने पिछले चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें 2017 का फाइनल भी शामिल है। सेमीफाइनल में शुक्रवार को उसका सामना इटली या ऑसट्रिया से होगा। अंतिम दो क्वार्टर फाइनल गुरुवार को होंगे, जिसमें जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से और स्पेन का सामना चेक गणराज्य से होगा। बर्ग्स ने फ्रांस के शीर्ष खिलाड़ी के खिलाफ शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और एक शानदार फोरहैंड विनर के साथ मैच को अपने नाम कर लिया। इससे पहले राफेल कॉलिग्नन ने कोरेंटिन मौटेट को 2-6, 7-5, 7-5 से हराकर बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिलाई थी।

दूसरे दौर में लक्ष्य, प्रणय, आयुष, मन्नेपल्ली और श्रीकांत

आस्ट्रेलियाई ओपन में भारतीय खिलाड़ियों की दमदार शुरुआत

एजेंसी ▶▶| सिडनी

लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय सहित पांच भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए 475,000 डॉलर इनामी आस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। लक्ष्य ने चीनी ताइपे के सु ली यांग को 21-17, 21-13 से हराया, जबकि प्रणय ने खराब शुरुआत से उबरते हुए पहले दौर के मैच में योहानेस सौत मार्सेलिनो को 57 मिनट में 6-21, 21-12, 21-17 से हराया।

लक्ष्य का अगला मुकाबला ची यू जेन या वांग त्जु वेई से होगा जबकि प्रणय इंडोनेशिया के आठवें वरीय अल्वी फरहान से भिड़ेंगे। आयुष शेट्टी ने कनाडा के सैम युआन को 33 मिनट में 21-11, 21-15 से पराजित किया। कर्नाटक के इस 20 वर्षीय खिलाड़ी का सामना दूसरे दौर में जापान के चौथे वरीय कोडाई नाराओका से होगा।

मन्नेपल्ली ने योहानसन को 66 मिनट में हराया

थारुण मन्नेपल्ली ने डेनमार्क के मैग्नस योहानसन को 66 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 17-21, 21-19 से हराया। राष्ट्रीय खेल 2023 के स्वर्ण पदक विजेता मन्नेपल्ली का अगला मुकाबला चीनी ताइपे के पांचवें वरीय लिन चुन-यी से होगा। किदांबी श्रीकांत भी 64 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के ली चिया हाओ को 21-19, 19-21, 21-15 से हराकर अगले दौर में पहुंच गए। इस वर्ष के शुरू में मलेशिया मास्टर्स में उपविजेता रहे श्रीकांत का अगला मुकाबला जापान के शोगो ओगावा या एडवर्ड लाउ से होगा।

किरण जॉर्ज ने की कड़ी चुनौती पेश

इस बीच किरण जॉर्ज को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद जापान के छठी वरीयता प्राप्त केंटा निशिमोतो से 21-11, 22-24, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। निशिमोतो ने पिछले सप्ताह जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराया था। मोहित जगलान और लक्षिता जगलान की भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी को एक अन्य मैच में कनाडा के नाइल याकुरा और क्रिस्टल लाई ने 12-21, 16-21 से हराकर बाहर कर दिया।

हेविट बनाएंगे 16 साल के बेटे के साथ जोड़ी, करेंगे टेनिस में शानदार वापसी

सिडनी। दो बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन लेटिन हेविट न्यू साउथ वेल्स ओपन एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता में अपने 16 वर्षीय बेटे क्रूज के साथ जोड़ी बनाकर प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगे। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी 44 वर्षीय हेविट ने 2001 में अमेरिकी ओपन और 2002 में विंबलडन जीता था। उन्होंने 2016 में आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चुनिंदा टूर्नामेंटों में युगल मुकाबलों में खेलना जारी रखा था। वह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की डेविस कप टीम के कप्तान भी हैं। पिता पुत्र की यह जोड़ी पहले दौर में आस्ट्रेलिया के ही हेडन जोन्स और पावेल मारिनकोव का सामना करेंगे।

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री:

-नए राजनीतिक समीकरणों के साथ 26 मंत्रियों ने संभाली जिम्मेदारी

पटना । नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे राज्य की राजनीति के केंद्रीय चेहरे बने हुए हैं। गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रतीक था, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बिहार की अहम भूमिका को भी रेखांकित कर गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी इस गठबंधन की मजबूती का स्पष्ट संकेत रही।

भव्य समारोह और राजनीतिक संदेश-

गांधी मैदान का ऐतिहासिक परिसर सोमवार को एक बार फिर गवाह बना जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। यह उनका दसवां कार्यकाल है, जो अपने-आप में देश की राजनीति में एक अनोखा कीर्तिमान है। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की ओर गमछा हिलाकर अभिवादन किया, जो यह दर्शाता है कि केंद्र और बिहार की नई गठबंधन सरकार पूर्ण तालमेल के साथ आगे बढ़ने का संदेश देना चाहती है। समारोह में हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नगालैंड, ओडिशा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यह उपस्थिति बिहार के राजनीतिक महत्व और नीतीश-मोदी समीकरण की मज़बूती का संकेत मानी जा रही है।

दो डिप्टी सीएम के साथ नई कैबिनेट-

इस बार बीजेपी ने बिहार में सत्ता संचालन के लिए दो उपमुख्यमंत्री देने का फैसला किया है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। दोनों नेताओं को संगठन और सत्ता संचालन का व्यापक अनुभव है, जो आने वाले समय में सरकार की नीतियों और फैसलों को गति देगा।

शपथ ग्रहण समारोह में कुल 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें—

14 मंत्री बीजेपी कोटे से
8 मंत्री जदयू से
2 लोजपा (रामविलास) से
हम से 1
कुशवाहा की पार्टी से 1

कैबिनेट में सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हुई है।

एकमात्र मुस्लिम चेहरा – जमा खान

इस बार भी जदयू के जमा खान को मंत्री बनाया गया है। वे इस मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम चेहरा हैं। इससे जदयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बनी रहेगी, भले ही संख्या कम हो।

कैबिनेट में 13 नए चेहरे-

इस बार मंत्रिमंडल में कुल 13 नए चेहरों को मौका दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रामकृपाल यादव और श्रेयसी सिंह की हो रही है। रामकृपाल यादव केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और बिहार में उनकी पकड़ मजबूत है। श्रेयसी सिंह, जो पूर्व शूटर और युवा नेता हैं, का मंत्री बनना बीजेपी के युवा वोटरों को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा मौका-

लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान इस समारोह में विशेष रूप से चर्चा में रहे। मंच पर उन्होंने जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर सम्मान जताया, जिससे गठबंधन की एकजुटता की छवि सामने आई।

चिराग की पार्टी को इस बार दो मंत्री पद मिले हैं। लोजपा (आर) से जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें संजय सिंह का नाम सबसे चर्चित है। वे महुआ सीट से चुनाव जीते हैं और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को मात दी थी।

शिवकुमार का बड़ा संकेत: KPCC अध्यक्ष पद छोड़ने की तैयारी

-कर्नाटक में CM पद की सियासी जंग फिर तेज

बेंगलुरु । कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को ऐसा बयान दे दिया, जिसने पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं को नई दिशा दे दी। इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिवकुमार ने कहा— "मैं इस पद पर हमेशा नहीं रह सकता। साढ़े पांच साल हो चुके हैं, मार्च में छह साल पूरे हो जाएंगे। अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए।"

उनके इस बयान को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है कि वे जल्द ही KPCC अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह फ्रंटलाइन लीडरशिप का हिस्सा रहेंगे। "चिंता मत करिए, मैं नेतृत्व में रहूंगा। मैं रहूं या न रहूं, इससे फर्क नहीं पड़ता," उन्होंने कहा।

पद छोड़ने के संकेत या सियासी चाल?-

शिवकुमार के इस वक्तव्य को सामान्य टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। बीते कुछ महीनों से यह चर्चा तेज है कि वे सरकार के आधे कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद रखते हैं। कर्नाटक में मई 2023 में कांग्रेस सत्ता में आई थी और इस महीने सरकार के 5 साल के कार्यकाल में ढाई साल पूरे होने वाले हैं। यह वही समय है जब सत्ता-साझेदारी मॉडल पर कांग्रेस ने पहले संकेत दिए थे— यानी कार्यकाल के बीच में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं। हालांकि पार्टी के आधिकारिक स्तर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस समझौते की चर्चा लगातार बनी हुई है।

सिद्धारमैया बनाम शिवकुमार— पुरानी रस्साकशी फिर चर्चा में-

शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच सियासी खींचतान कोई नई बात नहीं है। 2023 में सरकार गठन के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच सीएम पद के लिए गंभीर तनातनी हुई थी, जिसे कांग्रेस हाईकमान ने समझदारी से सुलझाया था। सिद्धारमैया को CM और शिवकुमार को डिप्टी CM व KPCC अध्यक्ष का पैकेज देकर संतुलन बनाया गया था। अब जब शिवकुमार खुद संकेत दे रहे हैं कि वे संगठनात्मक पद छोड़ने को तैयार हैं, यह माना जा रहा है कि वे सरकार में और बड़ी भूमिका— यानी मुख्यमंत्री पद— के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। उनका यह कदम एक तरह से हाईकमान को संदेश देने जैसा भी है कि वे नेतृत्व की पहली लाइन में बने रहना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: राज्यपाल बिलों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में साफ कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास होकर आने वाले विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते। यह फैसला उस पुरानी बहस को एक नई स्पष्टता देता है, जिसमें राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच विधेयकों को मंजूरी देने में होने वाली देरी को लेकर विवाद चलता रहा है।

राज्यपाल के पास सिर्फ 3 विकल्प – कोर्ट का स्पष्ट निर्देश-

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल के पास किसी विधेयक को लेकर सिर्फ तीन विकल्प उपलब्ध हैं: मंजूरी देना, विधानसभा को दोबारा विचार के लिए लौटाना, या फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देना। कोर्ट ने कहा कि इन तीन विकल्पों के अलावा 'बिल रोककर रखने' की कोई संवैधानिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि विधायी प्रक्रिया बाधित न हो और लोकतांत्रिक शासन में संतुलन बना रहे।

समय सीमा तय नहीं, पर देरी पर न्यायिक दखल-

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान में बिल की मंजूरी के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा तय नहीं की गई है। इसलिए कोर्ट किसी तरह की निश्चित डेडलाइन लागू नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी राज्यपाल द्वारा अनुचित देरी की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट स्थिति में दखल देने का पूरा अधिकार रखता है। यानी राज्यपाल अपनी संवैधानिक भूमिका का दुरुपयोग नहीं कर सकते।

तमिलनाडु विवाद से उठी थी पूरी बहस-

यह मामला तब तेज़ हुआ जब तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लंबे समय तक रोककर रखा था। राज्य सरकार का आरोप था कि यह कार्यपालिका के काम में असंवैधानिक दखल है और इससे प्रशासनिक कामकाज बाधित होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि राज्यपाल के पास किसी बिल को वीटो करने की शक्ति नहीं है। इसके बाद यह मामला और गंभीर हुआ, और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन मांगते हुए 14 सवाल भेजे थे।

राष्ट्रपति की भूमिका पर भी स्पष्टता-

इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई बिल राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि यह बात पहले 11 अप्रैल के आदेश में कही जा चुकी थी। राष्ट्रपति द्वारा स्पष्टीकरण मांगने और कई संवैधानिक प्रश्न खड़े होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने तक सुनवाई करके अब व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

फैसले का महत्व-

राज्यपालों द्वारा विधेयकों को रोककर रखने की प्रथा पर संवैधानिक रोक लगाई गई। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन को स्पष्ट किया गया। विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को खत्म करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की भूमिका को सीमित और परिभाषित किया गया, ताकि लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत रहे।

ट्रम्प बोले-350% टैरिफ की धमकी पर मोदी का फोन आया

-दावा- पीएम ने कहा 'वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे'

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़े दावे के साथ अंतरराष्ट्रीय हलकों में हलचल बढ़ा दी है। अमेरिका-सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने 350% टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रम्प के मुताबिक, सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का फोन आया, जिन्होंने कहा कि उनकी चेतावनी ने "लाखों लोगों की जान बचा दी।" ट्रम्प ने यह भी कहा कि शरीफ ने उन्हें बताया कि हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे और किसी भी वक्त स्थिति पूर्ण युद्ध में बदल सकती थी।

इसके बाद ट्रम्प ने दावा किया कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपर्क किया। ट्रम्प के अनुसार—

मोदी ने कहा, "वी आर डन... हम जंग नहीं करेंगे।"

ट्रम्प ने पूछा— "क्या खत्म कर चुके हो?"

इस पर मोदी ने जवाब दिया— "हम युद्ध नहीं करने जा रहे हैं।"

ट्रम्प का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण एशिया में सैन्य तनाव हाल ही में बढ़ा था। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था। यह ऑपरेशन पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया था, जहां कई महत्वपूर्ण टारगेट्स को निशाना बनाया गया। भारत की इन सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में पाकिस्तान भी सतर्क था और सीमाओं पर भारी सैन्य मूवमेंट देखा गया। हालांकि 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा हुई, जिससे स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी। ट्रम्प के इस ताज़ा बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में अमेरिका की आर्थिक दबाव की रणनीति ने युद्ध टाला? क्या मोदी और शरीफ के फोन कॉल्स ट्रम्प के बताए अनुसार हुए थे?।

अमेरिका-भारत रक्षा सौदा:

-100 जेवलिन 'टैंक किलर' मिसाइल और 216 एक्सकैलिबर स्मार्ट प्रोजेक्टाइल की बड़ी डील

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका ने भारत के साथ एक अहम रक्षा सौदा मंजूर किया है, जिसके तहत भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम (FGM-148) और 216 एक्सकैलिबर स्मार्ट प्रोजेक्टाइल (M982A1) मिलने जा रहे हैं। यह पूरा सौदा लगभग 92.8 मिलियन डॉलर (करीब 775 करोड़ रुपए) का है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने बताया कि इस डील की पूरी जानकारी और मंजूरी अमेरिकी कांग्रेस को भेज दी गई है, जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय हथियार बिक्री के लिए जरूरी प्रक्रिया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह हथियार भारत की सैन्य क्षमताओं को भविष्य की चुनौतियों और मौजूदा खतरों से निपटने में मजबूत बनाएंगे।

जेवलिन मिसाइल सिस्टम—टैंक और बख्तरबंद वाहनों का दुश्मन-

FGM-148 जेवलिन को दुनिया की सबसे आधुनिक और भरोसेमंद एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल माना जाता है। यह पूरी तरह पोर्टेबल है और सैनिक इसे कंधे से दाग सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है—हीट सिग्नेचर पहचानने की क्षमता। यानी यह मिसाइल अपने टारगेट की गर्मी को पहचानकर उस पर बेहद सटीक हमला करती है। यह तकनीक इसे उन हालात में भी कारगर बनाती है जहां धुआं, धूल, कोहरा या खराब मौसम हो। जेवलिन मिसाइल की रेंज लगभग 2500 मीटर है और यह "फायर एंड फॉरगेट" मोड में काम करती है। यानी मिसाइल छोड़ते ही सैनिक को दोबारा लक्ष्य पर नजर रखने की जरूरत नहीं—मिसाइल खुद-ब-खुद अपने टारगेट को लॉक कर लेती है। यह क्षमता इसे बंकरों, बख्तरबंद गाड़ियों और भारी टैंकों को भी आसानी से नष्ट करने में सक्षम बनाती है। भारत पहले से ही एंटी-टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, लेकिन जेवलिन जैसी उन्नत मिसाइल मिलने से उसकी इन्फेंट्री की मारक क्षमता और तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल—तोप से छोड़ा जाने वाला 'स्मार्ट बम'-

इस सौदे का दूसरा अहम हिस्सा है 216 M982A1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल। यह GPS-गाइडेड स्मार्ट गोलाबारूद है जिसे सामान्य तोप से दागा जाता है, लेकिन इसकी सटीकता और रेंज आधुनिक मिसाइलों जैसी ही होती है। साधारण तोप से दागे जाने वाले गोले 15–20 किलोमीटर तक ही असरदार होते हैं, लेकिन एक्सकैलिबर की रेंज 40–50 किलोमीटर तक है। इसकी सटीकता (पिनपॉइंट एक्यूरेसी) इतनी अधिक है कि कम गोला-बारूद में ही बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इससे दुश्मन की पोज़िशन, बंकर, हथियार भंडारण और ठिकानों को दूर बैठे हुए भी सटीकता के साथ नष्ट किया जा सकता है। यह तकनीक भारतीय सेना की आर्टिलरी यूनिट को आधुनिक युद्धक्षेत्र में और भी शक्तिशाली बनाती है, खासकर वे इलाके जहां सीधी लड़ाई के बजाय लंबी दूरी से प्रहार ज्यादा प्रभावी होता है—जैसे पहाड़ी क्षेत्र, सीमावर्ती पोस्ट, जंगल या कठिन भूभाग।

भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी का मजबूत संदेश-

हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की। इसका उद्देश्य आगामी बजट को लेकर इंडस्ट्री के सुझाव लेना था। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने कहा, "आगामी बजट 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ नौवीं प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की।" बयान में आगे कहा गया, "इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए।" आगामी बजट की तैयारियों के लिए वित्त मंत्री लगातार अलग-अलग सेक्टर्स से जुड़े लोगों के साथ बैठक कर रही हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की थी। इस बैठक का फोकस बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित था। इस बैठक में वित्त मंत्री के अलावा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी उपस्थित थे। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और शहरी विकास के प्रतिनिधियों के साथ 21 नवंबर को मुलाकात करेंगी। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए। वहीं, वित्त मंत्री ने बुधवार को तीसरी प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट के इनपुट के लिए चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्री-बजट चर्चा के तहत सरकार आने वाले बजट के इनपुट के लिए इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षकारों के साथ लगातार बैठक कर रही है।

सहकारिता क्षेत्र में चार गुना वृद्धि:

NCDC ने दी ₹95,200 करोड़ की वित्तीय सहायता - अमित शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 92वीं साधारण परिषद बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद देश के सहकारी क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता को नई दिशा मिली है और NCDC इस बदलाव का मजबूत आधार बनकर उभरा है।

सहकारिता से ग्रामीण भारत को मजबूती देने का लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीण परिवारों, मछुआरों, छोटे उत्पादकों और उद्यमियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसके जरिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत किया जा सकेगा।

NCDC का प्रदर्शन: चार वर्षों में 4 गुना वृद्धि

मंत्री ने बताया कि NCDC ने वित्तीय सहायता के वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसका कुल वितरण 2020-21 के ₹24,700 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹95,200 करोड़ हो गया है। यानी लगभग चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था ने पिछले चार वर्षों में वित्तीय समावेशन और नवाचार के नए मानक स्थापित किए हैं। NCDC ने 40% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है, नेट NPA शून्य रखा है और ₹807 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

अमित शाह ने कहा कि NCDC डेयरी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और विभिन्न मार्केटिंग फेडरेशनों के माध्यम से प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को किसान उत्पादक संगठन (FPO) के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

मत्स्य क्षेत्र में मजबूती और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा

NCDC ने मत्स्य क्षेत्र में 1,070 FFPOs को सशक्त बनाया है और 2,348 अन्य FFPOs पर काम जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात में गहरे समुद्री मत्स्य पालन के लिए उन्नत ट्रॉलर्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे मछुआरा समुदाय—विशेषकर महिलाओं—को आर्थिक सशक्तिकरण मिला है।

शुगर मिलों एवं डेयरी में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा

सरकार द्वारा शुगर मिलों के आधुनिकीकरण हेतु दिए गए ₹1,000 करोड़ के अनुदान के आधार पर, NCDC ने 56 शुगर मिलों को ₹10,005 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। इस सहायता में एथेनॉल प्लांट, को-जनरेशन और कार्यशील पूंजी शामिल है।

भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा — "भारत टैक्सी"

अमित शाह ने बताया कि NCDC देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा "भारत टैक्सी" शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए एक मल्टी-स्टेट सोसाइटी पंजीकृत हो चुकी है। ड्राइवरों के पंजीकरण और टेक्नोलॉजी विकास का कार्य जारी है।

महिला सहकारी समितियों और प्रमुख सेक्टरों के लिए विशेष फंड

केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए ₹2,000 करोड़ अनुदान के आधार पर NCDC ₹20,000 करोड़ के वित्तीय पैकेज के साथ रियायती ऋण उपलब्ध कराएगा। यह धनराशि विशेष रूप से डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कपड़ा और महिला सहकारी समितियों पर खर्च की जाएगी।

देशभर में नेटवर्क का विस्तार

NCDC ने विजयवाड़ा में नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख एवं पूर्वोत्तर राज्यों में कई उप-कार्यालय शुरू किए हैं। इससे सहकारिता नेटवर्क का विस्तार हुआ है और अधिक क्षेत्रों में सहकारी ढांचे को मजबूत आधार मिला है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,